Shri Chaturanan Mishraj agreed. But the Chair should not say that it will be the first item on that day. You can say this is postponed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY); That question will be considered.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: If a Member is present in the House and he does not move his Resolution, the Resolution automatically lapses.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I was prepared to move the Resolution but since there was a request from the Government, I have agreed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): That matter is over now. Mr. Mathur, you will now move your Resolution.

RESOLUTION RE: UNPRECEDENTED RISE IN THE PRICES OF ESSENTIAL COMMODHTES AS A RESULT OF HIKE IN ADMINISTERED PRICES

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): Sir, I move the following Resolution:—

""This House expresses its deep concern over the unprecedented rise in the prices of essential commodities as a result of hike in the administered prices of rice, wheat, sugar and petroleum products by Government and urges upon Government to take effective measures to check the steep rise in the prices of essential commodities so as to protect the common man, particularly the weaker sections of society from undue financial hardships."

श्रीमान्, बड़े खेद के साथ इस विषय पर आज हम लोग दोबारा बहस कर रहे हैं। महोदय, महंगाई के सवाल पर, एक बार नहीं मैं समझता हूं कि हर सेशन के अंदर बहस होती रही है और जब-जब यह विषय बहस में आया है, सरकार ने वायदा किया है कि हम महंगाई को कम करेंगे या घटा देंगे। हम सभी को स्मरण होगा कि 1991 के चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषणा पत्र छपा गया था और उसमें वायदा किया गया था कि हम सौ दिन के भीतर 10 परसेंट कीमतें कम कर देंगे, लेकिन कीमतें कम नहीं हुई। इसके साथ-ही-साथ यह भी उन्होंने वायदा किया था कि हम 10 बिलयन जॉब्स या काम लोगों के लिए पैदा करेंगे, लेकिन इस संबंध में भी कुछ नहीं किया गया क्योंकि कांग्रेस की सरकार का रवैया कभी भी आम आदमी के पक्ष में नहीं रहा। केवल ग्रेन-केन-प्रकारेण, किसी-न-किसी प्रकार से हम सत्ता में बने रह सकें और पैसा कमा सकें फिर चाहे वह बोफोर्स का स्कैंडल हो, चाहे वह स्कैम हो, उनकी निगाहें आम आदमी की तरफ न होकर अपने स्वार्थ और अपनी गद्दी पर रही हैं। यही कारण है कि जो वायदे वह करते हैं, वह पूरे नहीं होते हैं। महोदय, मुझे एक घटना याद आती है। बहुत दिन पहले की बात है, चांदनी चौक में एक तांगेवाला जा रहा था। उसने घोड़े की आखों पर प्लिंकर लगा रखा था। उससे पूछा कि, ये इसकी आंखों पर क्या लगाते हो? वह कहने लगा कि, मेरा घोड़ा बहुत होशियार है, मैं इसके लिए घास लाता हूं। यह हरी घास लाने का आदी है, मगर हरी घास नहीं मिलती। मैं सूखी घास ले आता हूं और हरे रंग का चश्मा लगा देता हूं। यह उसे हरी घास समझकर खा लेता है। उसी प्रकार से ये हर चुनाव में वायदा करते हैं, लेकिन वह वायदे पूरे नहीं होते हैं। इन्होंने भारत की जनता को एक ऐसा प्राणी समझा हुआ है जिसको जब चाहे धोखा दे दो।

फिर कीमतें कब बढ़ाई जाती हैं? अगर कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ें, बजट के बाद बढ़ें तो शायद आश्चर्य नहीं होगा। जैसे अभी 997 करोड़ के लाभ का, जिसमें सरकार को अर्निंग होगी रेलवे बजट आया, मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं, लेकिन 997 करोड़ की इस अर्निंग के बाद भी इनका पेट नहीं भरेगा क्योंकि हम जानते हैं कि हर साल का यह रवैया बन गया है। विगत तीन-चार सालों से यह रवैया हम देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और यह बजट के समय नहीं बल्कि बजट के पहले बढ़ाई जाती हैं ।

श्रीमन्, बजट का अर्थ क्या है? बजट का अर्थ है कि एक अमुक सरकार अमुक विषय में अमुक समय पर क्या करना चाहती है, क्या उसकी नीतियां हैं, क्या उनका परिणाम होना है, क्या प्रभाव होना है वह बताकर कार्य करे। लेकिन, एक नीति है, एक रवैया है कि असलियत को किस प्रकार छिपाया जाए। बजाय इसके कि बजट का घाटा दिखाया

जाए, जो डेफिसिट बजट रहता है उसे कैसे कम दिलाया जाए इस प्रकार की नीति को मद्देनजर रखते हुए ही कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि अभी जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, उससे अनुमान है कि लगभग 63 हजार करोड़ रुपया इन्होंने कमाया है। यह इस प्रकार से कि पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने से जितना मुनाफा होगा, जो सरकार को अर्निंग होगी अनुमानतः 2500 करोड़ की, मिट्टी के तेल से एक हजार करोड़ की, गैस से एक हजार करोड़ की और पी.डी.एस. यानि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से एक हजार आठ सौ करोड़ की और टोटल लगभग 63 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा पिछले दिनों बजट के पहले ही कीमतें बढ़ाकर सरकार ने प्राप्त किया है।

श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि यदि बजट का डेफिसिट इसी तरह से पूरा करेंगे तो काम कैसे चलेगा? यह घटाव क्यों होता है? घटाव का एक कारण है कि सरकार अपने खर्चों पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकी है। अगर देखा जाए तो जितने इनके अपने खर्चे हैं, वह खर्चे बढ़े हैं। यदि खर्चे न बढ़ते और सरकार अपने खर्चों को कम करती तो शायद इतना पैसा कमाने के लिए यह तीखा रास्ता नहीं अपनाना पड़ता। अगर हम निगाह डालें, इनके वायदों को देखें तो 1991 में चुनाव हुआ, 1991 से पहले के तीन साल और 1991 के बाद के तीन साल का रिकार्ड देखें तो सीधी स्थिति यह आएगी कि इन दिनों में 50 परसेंट से ज्यादा कीमत बढ़ी हैं हर चीज की, खाने की, पीने की, पहनने की चीजों में 50 फीसदी कीमतें बढ़ी हैं। उधर यह कहते हैं कि हमने मुद्रास्फिति को कम कर दिया। कब कम किया? जरा वर्ष 1989-91 का देखिए, उस वक्त इनफ्लेशन रेट 8.3 परसेंट था, जो 1992-93-94 में 10.5 परसेंट हो गया है। यह इनफ्लेशन कहां जा रहा है? पिछले दिनों शायद फाइनेन्स मिनिस्टर का, किसी का बयान आया था कि हमारा इनफ्लेशन रेट कम हो गया है। कम कहां हुआ है? थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन आज 10.5 परसेंट इनफ्लेशन रेट हो गया है। अब अगर कम हो भी जाए तो अर्थ क्या है? अर्थ तो यह है कि यदि किसी चीज की कीमत इतने प्रतिशत बढ़ रही है, बीच में उसके बढ़ने की रफ्तार कुछ कम हुई है वह ऐसे है कि जैसे कोई आदमी दौड़ता हुआ चला जाता है तो दौड़ते दौड़ते हांफने लगता है, लेकिन वह आगे तो बढ़ता ही है। यह बात अलग है कि उसकी रफ्तार घट जाए। इस बात का भरोसा लोगों को दिलाकर कि इनफ्लेशन रेट कम हो गया है, यह जो कुछ अर्थशास्त्री, इकोनोमिस्ट आंकड़ेबाजी करते चले जाएं, उससे आम जनता जो है, जिसको रोटी खानी है, जिसको बस में चलना है, जिसको कपड़ा पहनना है, उसको उन आंकड़ों से कोई संबंध नहीं है कि इनफ्लेशन रेट 8.3 है या 10.5 है। इस आंकड़बाजी से उसे कुछ लेना देना नहीं है। वह तो यह जानता है कि बाजार में उसे कपड़ा किस भाव में मिलेगा, उसका सवाल यह है कि उसे गेहूं बाजार में किस भाव में मिलेगा, वह जानना चाहता है कि उसे मिट्टी का तेल किस भाव मिलेगा? यदि आपका बजट या आपनी नीतियां उसे यह दिखा दें कि पहले वह दस रुपए अपनी जरूरत पर खर्च करता था, अब अपनी उसी जरूरत के लिए उस आठ रुपए खर्च करने हैं तो उससे आपको दाद मिलेगी, लेकिन यह कहना कि इनफ्लेशन रेट कम हो गया है और वह पहले जो दस रुपए में दिन चलाता था अब उसे पन्द्रह रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो इस प्रकार के धोखे से काम नहीं चलेगा। आखिर, कारण क्या है? कारण बहुत से हैं। नंबर एक, आपने नीति बदली है। हमने तो पढ़ा है कांग्रेस का कभी सोशलिज्म आता था, कभी समाजवाद, कभी दूसरा, कभी तीसरा, ऐसे समाजवाद के रूप बदलते रहते थे।

अभी आपने अपनी सारी जिंदगी बिताने के बाद नीति बदली है ...(व्यवधान)...

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): रूप बदल जाता है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: बिल्कुल बदल गया है, मैं मानता हूं क्योंकि आपकी जो 1885 में पार्टी थी या 1947 में थी, वह आज नहीं रही। पहले गांधी जी की पार्टी हो सकती थी, इमानदारों की पार्टी मानी जा सकती थी, आप ठीक कह रहे हैं कि रूप बदल जाता है। आपका रूप बिल्कुल बदल गया है। ...(व्यवधान)... कारण क्या है? नीति बदली है आपने, ऐसा पलटा खाया है कि लोग कहते हैं आश्चर्य है, यह पहली कांग्रेस है, गांधी जी की है, जवाहर लाल की है। फिर कहते हैं कि यह राव साहब की सरकार है, राव साहब की सरकार को सब जानते हैं कि क्या है। बड़े-बड़े कार्टून निकलते हैं मैं इसका जिक्र क्या करूं, लेकिन किसी ने दुर्भाग्य से कार्टून नहीं निकाला, अच्छा होता कि इस सरकार को शीर्षासन करते हुए दिखा देते कि पहले ऐसे खड़ी थी, अब ऐसे खड़ी है। पहले समाजवादी थे, अब समाजवादी नहीं हैं, पुराना जो स्वतंत्र पार्टी का मेनिफेस्टो है, शायद उससे आगे बढ़ने की नीति में है। जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, हम हमेशा से ही, जब जनसंघ थी, उस समय से कहते आए हैं कि लिब्रलाइजेशन होना चाहिए, यह जो जकड़ है सरकार की अर्थव्यवस्था पर, यह कम होनी चाहिए, लेकिन उस समय

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

हमें कहते थे ये समाज विरोधी हैं। ये तो केवल पैसे वालों के समर्थक हैं। नहीं, क्योंकि आपने असलियत को समझा नहीं, उस समय आपने एक काला चश्मा आंखों पर लगा रखा था। उसको आपने उतारा है, अच्छा किया है। लेकिन उतारा कबसे है? आपने उतारा है ऐसे कि लिब्रलाइजेशन किया, विदेशियों के लिए तो फाटक खोल दिए कि आइए यहां कोका कोला लाइए, फ्लां लाइए, लेकिन अंदर की जो इंडस्ट्री है, उसके लिए आपने रास्ते खोले नहीं है। परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा और पैसा बाजार में आ रहा है। क्यों आ रहा है पैसा? क्योंकि आपने दरवाजे खोल दिए हैं। अंदाजा है कि करीब 300 करोड़ रुपया आ चुका है विदेशी मुद्रा के रूप में। विदेशी मुद्रा आती है तो जाती कहां है? रिजर्व बैंक में जमा होती है, रिजर्व बैंक में 300 करोड़ रुपया आ गया और आप कहते हैं कि हमारा बैलेंस आफ पेमेंट ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप आंखें बंद करते हैं। आप उधार लेते हैं अथवा विदेश से पैसा लाने के बाद आप अपना बैलेंस ठीक कर लेते हैं लेकिन उसका बाजार पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका आप अंदाजा नहीं लगाते। जिस एन.आर.आई. ने, हमारे विदेशी व्यक्ति ने पैसा दिया है, वह आता है, पैसा देता है डालर में और लेता है रुपए में। तो रुपया लेकर जब बाजार जाएगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। आप लोगों को अंधेरे में रखना चाहते हैं, यह कहते हैं कि हमने विदेशी मुद्रा ले ली है लेकिन विदेशी मुद्रा लेने के बाद आपने कोई व्यवस्था की है कि उसका दुष्परिणाम बाजार में न पड़े? पड़ा है। कभी "स्कैम" के जरिए हो, वह बात अलग है, लेकिन इसका दुष्परिणाम तो न पड़े।

दूसरे आपका प्लान एक्सपेंडिचर तो कम है लेकिन उसके साथ आपका जो अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, वह बढ़ रहा है। आखिरकार इसका जब तक आप मेल नहीं बैठाएंगे तब तक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।

एक-आध बात मैं और कहूंगा, बहुत लम्बी बात करना नहीं चाहता। पैट्रोल की बात लीजिए। पैट्रोल की कीमतें आपने बढ़ा दीं दिल्ली में पहले कीमत थी 15.71 रुपए और अब है 16.78 रुपए। ऐसे ही कलकत्ते का, बम्बई आदि का है, उनको पढ़ूंगा तो देर लगेगी, मैं पढ़ना नहीं चाहता। आपने पैट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ाई हैं? आप कहते हैं कि आपका पूल का फंड कम हो गया है, मगर क्यों हुआ है? अजीब तमाशा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तो पैट्रोल की कीमतें घट रही है और पूल के फंड में घाटा हो रहा है।

डा0 नौनिहाल सिंह (उत्तर प्रदेश): 100 करोड़ की बचत है, 100 करोड़ कम हो गया है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: देखिए, मेरे साथी कह रहे हैं कि 100 करोड़ कम हो गए हैं।

मुझे याद है जब चन्द्रशेखर साहब की सरकार थी। इस बात पर जब इराक और कुवैत का युद्ध हुआ, उस पर 75 परसेंट एक प्रकार से लेवी लगा दी थी और यह कहा था क्योंकि सरकार तो सरकार होती है, जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार ठीक होगा हम लेवी कम कर देंगे। मगर आपने कम नहीं की। कम क्यों नहीं की, मैं पूछना चाहता हूं जबकि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कीमतें कम हो रही हैं। इतना ही नहीं, आपने अपनी सरकार बनाने के बाद तीन बार पैट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। 1991 में क्या हुआ? तब कीमतें क्यों बढ़ाईं? कौन इसका जवाबदेह है? जवाबदेह आप हैं। पैट्रोल के अंदर डेफिसिएट क्यों है, इसकी जानकारी आप मुझे देने की कृपा करें।

दूसरा सवाल, आपने गेहूं के, चावल के तथा अन्य खाने की चीजों की हरएक की कीमतें बढ़ादीं। क्यों बढ़ाईं? आप कहते हैं कि पी.डी.एस. की जो दुकानें हैं उन्हें घाटा हो रहा है। कौन घाटा कर रहा है? क्या दुकानदार कर रहे हैं? कौन कर रहा है? जो ग्राहक हैं, क्या वह कर रहा है? नहीं, यह घाटा लगातार आपकी इन एफिशिएंसी कर रही है, आपकी व्यवस्था खराब है इसलिए आपको पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में हानि उठानी पड़ रही है। यह जिम्मेदारी किसकी है? यह आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरा न करे, व्यवस्था ठीक न करे और उसका बोझ आप आम आदमी पर डालदें तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है। क्योंकि आपके पास न तो व्यवस्था है अनाज के रखने की। इस बार फसल अच्छी हुई है। वह फसल कहां रख रहे हैं? वह खुले मैदान में पड़ी रहती है, खराब हो जाती है। खराब आप करें और भुगते गरीब और जिस गरीबों के लिए आपने कहा है कि हम सस्ती दुकानें देंगे। गलती तो आप करें और गरीब आदमी इसको भुगते। वह अपनी जिंदगी में मुस्किल उठाए। उसके पास धन नहीं है तो वह खाए कहां से? इसलिए जिम्मेदारी आपकी है। फिर ट्रांसपोर्ट कहां से होता है? आज आप देख लीजिए जितने आपके गोदाम हैं उनसे कहां-कहां भेजा जाता है, कहां जाता है, यहां से वहां, वहां से यहां। व्यवस्था ऐसी है कि ट्रांसपोर्ट में समय लगता है, तो वह छीजन की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ग्राहक की है या दुकानदार की है? दुकानदार कहता है कि मुझे मुनाफा नहीं है, ग्राहक कहता है कि मुझे पैसा मिलता नहीं है। लेकिन आप अपने-आपको सुधारने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है। कहां

से कहां जाता है, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको कहना चाहूंगा बजाय इसके कि आप कीमतें बढ़ाएं, आपको चाहिये कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में अपनी कमजोरियों को कम करें। अगर कम नहीं करेंगे तो लोग मानने वाले नहीं हैं। कल आप चुनाव हार जाएंगे, वैसे भी हारेंगे। लेकिन इससे तो कम से कम ही पब्लिक आपके विरोध में होगी। मैं कुछ कीमतें देना चाहता हूं। होलसेल प्राईस इंडेक्स करके लोग आंकड़ेबाजी करते हैं। उसका भी आपको उदाहरण देना चाहता हूं। होलसेल प्राईस इंडेक्स 1982 में .03 था। अगर उसका बेस मानलें तो आज 251.9 परसेंट है। कहां 1982 में .03 और आज 1994 में 251.9 परसेंट है। यह क्या है? लेकिन अब आप कहेंगे कि यह तो पुरानी बातें कह रहे हैं। मैं अभी की बात कहता हूं। आपका एस्टीमेट था आज होलसेल प्राईस इंडेक्स इस महीने की 5 या 10 तारीख तक 250.3 परसेंट होगा। लेकिन हुआ कितना-251.9 परसेंट। यह परसेंटेज कहां बढ़ा है। आपका अनुमान तो खुद गलत हो रहा है। पैट्रोल की कीमतें 11 परसेंट बढ़ी हैं, खाद की कीमतें उससे भी ज्यादा बढ़ी हैं। मैन्युफैक्चरर्स गुड्स की कीमतें कम से कम .4 परसेंट बढ़ी हैं। पहले 245.6 था, आज उसका 245.5 है। मैं कनक्लूड करना चाहता हूं दो-तीन बातें कह कर।

महोदय, मैं दो-तीन बातें कहकर कनक्लूड करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने अभी एक कमेटी बनाई है प्लानिंग कमीशन के कहने पर बीजू पटनायक की अध्यक्षता में। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है? आप कितना अपनी कमर को कसना चाहते हैं इस समस्या को दूर करने के लिए ? गृह मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, वे सदन के नेता हैं। वे मुझे बता दें कि बीजू पटनायक की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट का हश्र क्या हुआ? मेरी जानकारी में तो रिपोर्ट आ चुकी है। उस पर आप कब तक कार्यवाही करेंगे और क्या आपके पास कोई योजना है कि आपने जो कीमतें बढ़ाई हैं, उनको 6 महीने में घटाएंगे? इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मेरी बात का जवाब दें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri S. S. Ahluwalia not present. Shri Ram Ratan Ram.

श्री राम रतन राम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। सरकार ने जो चावल, गेहूं, चीनी और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बढ़ोत्तरी की है, वह वास्तव में गरीब जनता के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर बहुत बड़ा भार है।

महोदय, जब भारत आजाद हुआ था, उस समय खाद्यान्न का उत्पादन 50 मिलियन टन था और हमारी पापुलेशन करीब 36 करोड़ थी। आज के युग में जब कि पापुलेशन 80 करोड़ से ज्यादा है, हमारा खाद्यान्न का प्रोडक्शन 190 मिलियन टन के करीब है। यह प्रोडक्शन हमारे किसानों की मेहनत का फल है, हमारे किसानों की लगन का फल है कि उन्होंने इतना उत्पादन करके भारत की बढ़ती हुई आबादी के खाने का इंतजाम किया।

महोदय, सरकार गेहूं और धान के समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है। चीनी मिलों के लिए गन्ने के मूल्य का निर्धारण करती है और यह आशा की जाती है कि उत्पादन करने के पश्चात मिलें अपने उत्पाद को निर्धारित कीमत पर बेचेंगी और उनसे एक तरह का इनडॉयरेक्ट कांट्रैक्ट होता है। किसानों से निर्धारित मूल्य पर गन्ना लेकर मिलों को दिया जाता है और मिलों से निर्धारित कीमत पर चीनी खरीदकर गरीब जनता के बीच में वितरित करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है लेकिन जब चीनी का मूल्य बढ़ता है तो किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता है। किसको यह लाभ मिलता है? जो किसान उत्पादन करता है, उसको तो लाभ नहीं मिलता। उसी प्रकार से गेहूं का समर्थन मूल्य आपने 350 रुपये किया है और 75 रुपए बढ़ा दिया है लेकिन समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। न जनता को फायदा हुआ, न किसानों को फायदा हुआ। यह किसके फायदे के लिए बढ़ाया गया है? यह तो गरीब जनता के ऊपर अनावश्यक भार पड़ गया है।

इसके साथ ही हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, उन पर अधिकाधिक भार पड़ा है। सरकार ने अगर गेहूं का मूल्य बढ़ाया, चावल का मूल्य बढ़ाया, पैट्रोल का मूल्य बढ़ाया तो उसके साथ-साथ दैनिक वेतनभोगी मजदूरों के मिनिमम वेजेज में भी उसको बढ़ोत्तरी करनी चाहिये थी और सरकारी कर्मचारियों के डी.ए. में भी वृद्धि करनी चाहिये थी। इसी तरह से पेंशनर्स की पेंशन में भी वृद्धि करनी चाहिये थी जिससे कि उनको रिलीफ मिल सके।

3.00 P.M. मेरे निवास स्थान के सामने फेयर प्राइस शाप है। वहां गरीब जब जाता है तो बढ़े हुए दाम देखकर वह क्रोधित होता है और सरकार को जिन शब्दों में आशीर्वाद देता है, वह मैं कह नहीं सकता। सरकार

[श्री राम रतन राम]

को कर्स करते हुए वह चला जाता है। मैं चाहूंगा कि जिन किसानों ने अपनी मेहनत से गेंहूं का इतना उत्पादन किया, अगर उस का दाम आपने बढ़ाया है तो समर्थन मूल्य से अधिक दाम उसको भी देना चाहिये, उसको कहना चाहिये कि हमने इतना दाम बढ़ाया है चलो तुमको भी इसमें इतना प्राफिट मिलेगा। तुमको भी हम फायदा दे रहे हैं तब तो बात समझ में आती। अगर एक तरफा दाम सरकार बढ़ाती जाए और किसान को उसका फायदा न दे तो प्राइवेट व्यापारी में और सरकार में क्या अंतर रह जाता है? इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वह दाम को घटाए नहीं तो बढ़ी हुई कीमतों के लिए लोगों को रिलीफ दे।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने इस विषय में मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदय, यह अत्यंत खेद की बात है कि हर वर्ष मंहगाई पर हम लोग बातें करते हैं। अभी-अभी जब मैं इस विषय पर बोलने के लिए अपना नाम दे रही थी तो मैंने अपने एक वरिष्ठ साथी से पूछा कि आप इस पर बोलेंगे, तो हमारे वरिष्ठ सांसद ने कहा कि मैं इस पर गत वर्ष बोल चुका हूं और पिछले 40 साल से महंगाई पर यहां बात हो रही है लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही है।

महोदय, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में हर वर्ष यह दावा करती थी और गत वर्ष भी दावा कर चुकी है कि वे सौ दिन के अंदर महंगाई को खत्म कर देंगे। किन्तु भारत जैसे देश में ऐसी घोषणा करने से क्या होता है? कांग्रेस के पास कोई जादू की छड़ी है, या हमारी वर्तमान सरकार के पास कोई जादू का करिश्मा है जिससे वह भारत की आम जनता को सुख के साधन उपलब्ध करा सके? आए दिन हम देखते हैं कि चीजों के दाम बढ़ते हैं। अभी बजट आने से पहले ही पैट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई, डीज़ल की कीमतें बढ़ाई गई और उसके बढ़ने से तमाम यातायात के सभी साधन महंगे हो गए और यातायात के साधन महंगे होते ही सब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। पेट्रोल, गैस, चावल, गेहूं, प्रारंभिक जरूरत की चीजों की कीमतें बढ़ गई जिससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वह अपनी आमदनी में अपने परिवार का खर्च चलाने मे असमर्थ हो जाता है। उस के लिए चावल और गेहूं जैसी आम जरूरत की चीजें एक सपना बन जाती हैं। बड़े दुख की बात है कि आपके इतने लंबे शासन के दौरान जनता के लिए आवश्यक चीजें, भोजन, आवास, वस्त्र और शिक्षा, ये सारी मयस्सर नहीं हो पाई हैं। गरीबी की रेखा के नीचे देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या के लिए ये चीजें कल्पना मात्र रह गई हैं। अगर हम बाजार में सर्वे करने जाएं तो यह बात दिखाई पड़ती है। एक गरीब आदमी जो सब्जी बेचता है उससे यदि पूछा जाए कि वह क्या यह सब्जी खुद खा रहा है तो वह बड़े खेद के साथ कहता है कि मुझे सब्जी खाने का सौभाग्य कैसे मिल सकता है। जब उसे इतनी ऊंची कीमत पर लाकर बेचता है तो उसको उसकी लागत भी नहीं मिलती। अगर सरकार कीमतें बढ़ाती जा रही है तो उसे वस्तुओं को भी उचित मूल्य पर वितरित करे। उसे मजदूरों के वेतनमान निश्चित करने चाहियें, लोगों का महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहिये जिससे कि बढ़ती हुई कीमतों से वे राहत पा सकें। अगर यह सरकार कुछ नहीं कर पाती है तो इसे जनता को धोखे में रखने का कोई अधिकार नहीं है।

धन्यवाद।

प्रो॰ विजय कुमार मलहोत्रा (दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदय, बजट आने से 10-15 दिन पहले कीमतों के अंदर इतनी बढ़ोतरी करना देश की जनता पर 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बोझ डालना यह बजट के साथ मजाक है। बहुत बार इस बात को कहा गया है कीमतों के अंदर वृद्धि बजट के घाटे को पूरा करने के लिए नहीं की जानी चाहिए। जो एडमिनिस्टर्ड प्राइसेज हैं जिनकी कीमतें सरकार स्वयं तय करती है उन कीमतों का एक तरीका है। उन कीमतों में अगर कोई ऐसी बात हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई ऐसी बात हो जाए कि मजबूरी हो जाए तो बात समझ में आती है। परन्तु अपना घाटा पूरा करने के लिए, केवल अमीर आदमियों को राहत देने के लिए, गरीबों का खून चूस कर एडमिनिस्टर्ड प्राइस को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जब राजस्थान के अंदर गये थे तो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के बारे में एक मीटिंग की थी। उसमें उन्होंने कहा कि मैं पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए गरीब आदमी को राहत देने के लिए यहां पर आया हूं। उन्होंने कहा पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम सारे हिन्दुस्तान में बढ़ा दिया जायेगा। और सब जगह पर गरीबों को उसके माध्यम से सस्ती चीजें देंगे। परन्तु कीमत जो बढ़ाई है पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में, राशन में, गेंहू की और चावल की उसमें और बाजार के अंदर मिलने वाले गेहूं और चावल की कीमत में कोई अंतर नहीं रह गया है बल्कि बाजार में इनकी कीमत कम है। इसमें पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम क्या करेगा। उसकी जरूरत ही नहीं रह गई है। गरीब आदमी के ऊपर बड़ा बोझ डाल दिया गया है। जो उसके माध्यम से राहत थी

उसको खत्म कर दिया गया। आप देखें इस बात को कि पहले राशन में गेहूं का मूल्य था 330 रुपये उसको बढ़ा कर 402 रुपये कर दिया गया। यानी 72 रुपये एक क्विंटल गेहूं के अंदर राशन में बढ़ोतरी कर दी गई। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। सरकार ने यह कहा है कि सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है। गेहूं की सपोर्ट प्राइस में 40 रुपये की बढ़ोतरी की है। आपने यह क्यों कि है? गेहूं के लाने ले जाने की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके गोदाम पहले से ही है। आपके ओवरहैड चार्जेज कहां से बढ़ रहे हैं? 40 रुपये सपोर्ट प्राइस बढ़ायें तो यहां पर 72 रुपये कीमत के अंदर बढ़ोतरी हुई है। 32 रुपये आप अपना घाटा पूरा करने के लिए सब्सिडी को खत्म कर रहे हैं। देश में कुल 90 लाख टन, तकरीबन 900 लाख क्विंटल गेहूं राशन में जाता है। इसमें अगर 72 रुपये की बढ़ोतरी की है तो कुल मिलाकर 648 करोड़ रुपये बनता है। 648 करोड़ रुपये आप एक साल के अंदर गेहूं के मूल्य में बढ़ोतरी करके वसूल करेंगे। चावल के अंदर कुल मिलाकर 437 रुपये से 537 रुपये कीमत कर दी है। 497 रुपये से 617 रुपये, 518 से 648 रुपये यानी 100 रुपये से लेकर 130 रुपये की बढ़ोतरी की है फी क्विंटल। यह तकरीबन कुल मिलाकर 100 लाख टन लगता है यानी एक हजार क्विंटल। यह कुल मिलाकर 1200 करोड़ रुपये बनता है। दोनों को मिलाकर तकरीबन 2000 करोड़ रुपये राशन की दुकान पर मिलने वाले गेहूं और चावल से मिलता है। यानी इतना बोझ आपने गरीब पर डाल दिया है। सात महीने पहले भी राशन की चीजों की कीमतों में बढ़तोरी की थी इसी सरकार ने। वह बढ़ोतरी कुल मिलाकर 414 करोड़ रुपये गेहूं में 800 करोड़ रुपये चावल में यानी 1200 करोड़ रुपये और पिछले महीने राशन की दुकान पर मिलने वाली चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी करके 2000 करोड़ रुपये गरीब जनता पर बोझ डाला यानी कुल मिलाकर 3000 करोड रुपये का बोझ एक साल में गरीब जनता पर पड़ा है। अगर वर्ल्ड बैंक आप से यह कहता है, इन्टरनेशनल मोनेटरी फंड यह कहता है कि गरीब आदमी को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दो तो हम इतने घुटने टेक देते हैं, उनके सामने इतने ज्यादा झुक जाते हैं....। कि हम अपने गरीब से गरीब आदमी पर तीन हजार करोड़ रुपये का बोझ डालते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, उसके बाद पेट्रोलियम के अंदर और चीनी के दामों में 75 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। चीनी के दाम जो अभी बढ़ाये हैं, उसको अगर देखें तो उसमें करीबन 900 करोड़ रुपये बढ़े हैं। गैस के अंदर 10 रुपये बजट से पहले ही बढ़ा दिये हैं। तो चीनी पर बढ़ोत्तरी, गैस पर बढ़ोत्तरी और पेट्रोलियम आइटम्स पर बढ़ोत्तरी। पेट्रोलियम आइटम्स पर जो वृद्धि हुई है उससे 25 सौ करोड़ रुपये एक साल में आयेगा। पर यह 1992 की कीमतों पर है और जो 1994 में आने वाला है, उसमें 4 हजार करोड़ रुपया सरकार को इसमें से मिलेगा। कुल मिलाकर जो मैंने आपके सामने आंकड़े दिये हैं उनके अनुसार दस हजार करोड़ रुपये का बोझ बजट से पहले एडमिनिस्टर्ड प्राइस में लगा दिया है। यह जो पेट्रोल की कीमत बढ़ायी, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि अगर और चीजों की कीमतें बढ़ जाती तो बात समझ में आती लेकिन यह बात समझ में नहीं आयी कि पेट्रोल की कीमतें, क्रूड आयल की कीमतें क्यों बढ़ायी गयीं? अगर पेट्रोल उत्पादन करने वाले देश इसकी कीमतें बढ़ा देते तो बात समझ में आती कि चलिये वहां पर इसकी कीमतें बढ़ गयी है, इसलिये हम भी यहां पर बढ़ा रहे हैं। परन्तु आज तक के इतिहास में सबसे कम कीमत दुनिया में इस समय क्रूड आयल की है। यह वहां पर 13.8 डालर पर बैरल बिक रहा है। इसकी कीमत इतनी नीचे कभी नहीं गयी। उधर तो पेट्रोल और क्रूड आयल की कीमतें गिर रही हैं और हिन्दुस्तान में इसकी कीमत बढ़ती जा रही हैं। अपने बजट के घाटे को इस तरह से कोई देश पूरा करे यह बजट का सबसे गलत तरीका है, यह एक धोखा देने वाला तरीका है कि बजट में अपने घाटे को पूरा करने के लिये आप एडमिस्टिर्ड प्राइस बढ़ा दें। एडमिनिस्टर्ड प्राइसेज बढ़ाने के लिये, खासकर जिनका नाम आप बार-बार लेते हैं, महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं एक तरीका आपको बताता हूं और वह तरीका यह है कि अगर किसी जगह पर कभी भी आपको किसी ऐक्शन के बारे में यह मालूम करना हो हमारा यह ऐक्शन ठीक है या गलत है तो यह देखो कि उससे गरीब से गरीब आदमी, सबसे गरीब आदमी पर उसका क्या असर पड़ता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां इसका सबसे गरीब आदमी पर बुरा असर पड़ा है कि जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग है, जिनको मजदूरी नहीं मिलती, जो भुखमरी से ग्रसित रहते हैं, जो बेकार हैं वह राशन की दुकान में जब राशन लेने जाते हैं तो उसके ऊपर आप इतना और भार बढ़ा दिया और छूट किनको दी है? छूट उन लोगों को दी है जो मोटर गाड़ियों पर बैठकर चलते हैं, मोटर गाड़ियों पर छूट देते हैं, एयर कंडीशनर्स पर छूट देते हैं। ऐसी चीजों पर आप इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी कम कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं। जितने ये अमीराना चीजें हैं, जितनी ऐयाशी की चीजें हैं, जिनका हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े धनपति इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर आप ये सारी छूट देते चले जा रहे हैं। आप बड़े जोर से नारा लगा रहे हैं कि कारपरेट टैक्स को 39 परसेंट ले आयेंगे, कारपरेट टैक्स कम कर देंगे, हम फलानी चीज पर कम कर देंगे।

[प्रो॰ विजय कुमार मलहोत्रा]

लेकिन जहां केवल एक परसेंट लोग हिन्दुस्तान में इन्कम टैक्स देते है और उनमें से भी अधिकांश देते नहीं, उनके लिये आप अपने बजट में से सारी कलाबाजियां करते हैं। हिन्दुस्तान में रहने वाले 90 करोड़ लोग जो इस समय हिन्दुस्तान में रहते हैं, उनमें से 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं और 80 प्रतिशत लोग गरीब हैं और लोअर-मिडिल क्लास के है, उनके ऊपर आप इस तरह से बजट से पहले इतना बड़ा बोझ डाल देते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, पेट्रोल की कीमत बढ़ गयीं, डीजल की कीमत बढ़ गयी, रेल-माल भाड़े बढ़ गये तो इससे गरीबों के काम आने वाली जितनी चीजें हैं उनके दाम भी बढ़ जायेंगे। अभी हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स साढ़े आठ प्रतिशत के करीब पहुंचा हुआ है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पिछली बार कहा था कि यह पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा लेकिन यह साढ़े आठ प्रतिशत हो गया। जो रिटेल प्राइसेज है, मेरे पास लेबर, ब्यूरो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यहां पर इसमें प्लसेज और प्रोडक्ट् का इंडेक्स जो 275 था वह 350 हो गया है। यह दिसम्बर 1992 में 275 था जो अब 350 हो गया है। इस प्रकार इसमें साढ़े सत्ताईस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सीरियल और प्रोडक्ट्स में 14 परसेंट की वृद्धि हुई है। कार्डिमम में 24 प्रतिशत वृद्धि है। दवाइयों में बहुत सी दवाइयों की कीमतें बढ़ायी जा रही है। गरीब आदमी बिना दवाइयों के मर रहे हैं। आपने अस्पतालों में यह व्यवस्था कर दी कि वहां पर मुफ्त दवा नहीं दी जायेगी क्योंकि वर्ल्ड बैंक आपसे कह रहा है कि हास्पिटल में दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करो। इसलिये आप हस्पतालों के अंदर मुफ्त दवा देना बंद कर रहे हैं।

अस्पतालों में टेस्ट करना बन्द कर रहे हैं। उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। उसके ऊपर दवाइयों की कीमतें दुगुनी से ऊपर चली गई है। महोदय, पिछली बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा था कि मैं चीजों में बड़ी-बड़ी छूटें दे रहा हूं और यह छूटें कंज्यूमर्स तक पहुंचे। क्या कोई छूट कंज्यूमर तक पहुंची? पिछले साल आपने हज़ारों चीज़ों पर राहतें दी थीं। आम यूज़ की चीजें कास्मेटिक्स, टूथपेस्ट और आयल्स पर एकदम बेइंतहा छूट दी, टेलीविज़न पर छूट दी लेकिन किसी छूट का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिला। बार-बार फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर यह छूट उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंची तो हम बड़े-बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, हम इसको देख रहे हैं। एक साल के बाद फिर वही दोहराया जा रहा है। यह किस के खिलाफ एक्शन कैसे लेंगे? उनके इकट्ठे किये हुए पैसे से चुनाव लड़ते है, जो उनके कब्जे में रहते हैं, जो उनके पांव तले दबे हुए हैं, वह उनके ऊपर कार्यवाही कहां से करेंगे? यह सारे के सारे जितने बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, उनको राहतें देने के लिए आप गरीब आदमी पर इस तरह से टेक्स पर टेक्स लगाते चले जाएं, यह उचित नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर यह नया तरीका शुरू किया गया है और यह सारा तरीका अगर आप देखें, श्री माथुर ने जो प्रस्ताव यहां पर रखा है, पूरे सदन का ध्यान आकर्षित किया है, संसद सदस्यों को यह देखना चाहिये कि कीमतों में वृद्धि होने से आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारियों के डी.ए. में आपने वृद्धि नहीं की क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को जो डी.ए. मिलता है, उसमें से यह चीज़ें निकाल दी जाती हैं। यदि चीनी के दाम बढ़ेंगे तो आम आदमी के लिए चाय की कीमत बढ़ जाएगी। मज़दूर, रिक्शा चलाने वाले, झल्ली उठाने वाले, पल्लेदार और झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को आप जा कर देखिये। यहां पर बड़े-बड़े मल्टीनेशनल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कोका-कोला हिन्दुस्तान में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे झुग्गी-झोंपड़ी वालों को क्या लेना देना है। अगर उसकी बस का किराया दुगुना हो जाए या उसको मिलने वाली चीज़ों के दाम दुगूने हो जाएं, दवाइयों के दाम दुगने हो जाएं बाज़ार में और रिक्शा चलाते हुए उसको वही एक रुपया मिले तो वह कैसे जिन्दगी बिताएगा। कितने लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं और आत्म हत्या कर रहे हैं। इस आत्म हत्या का पाप किन लोगों के ऊपर लगेगा जो गरीब आदमी पर इस प्रकार एडमिनिस्टर्ड प्राइसेज़ बढ़ा कर गरीब आदमी के इस्तेमाल की चीज़ों के दाम इस तरह से बढ़ाते हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा निंदनीय बात और धिक्कार की बात नहीं हो सकती है। सरकार द्वारा आने वाले बजट में जो बड़ी-बड़ी राहतें अमीरों को दी जाने वाली हैं उससे पहले इनको विदड्रा करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माथुर जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, महंगाई एक ऐसे शब्द का नाम है जिसके साथ जुड़ी हुई है देश की गरीबी और बेकारी। महंगाई शब्द का प्रयोग कोई अमीर आदमी नहीं करता है। अमीर आदमी जब बाज़ार में कोई चीज़ खरीद-फ़रोख्त करने जाता है तो उसको महंगाई महसूस नहीं होती है। महंगाई गरीबों के कष्ट का नाम है, बेकार लोगों के कष्ट का नाम है और यह एक रोग है। रोग क्यों है कि हमारा भारत एक गरीब मुल्क है। जिस भारत में 40 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे रहते हों वहां महंगाई की पुकार, हम लोग राजनीतिज्ञ हैं, हो सकता है किसी अपने राजनैतिक

स्वार्थ के लिए ज़ोर–ज़ोर से चिल्ला–चिल्ला कर कहते हैं पर कभी हम यह सोचें कि जो यह वेज और प्राइस का स्पाइरल का जो नेगेटिव साइकल हमारी सोसाइटी का, हम जब भी सरकार के सामने या देश के सामने कोई मांग रखते है उस मांग को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उन कुछ चीज़ों को लाने के लिए कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ती है। जब कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो उसका सेल प्राइस भी बढ़ता है। यह नेगेटिव साइकल बहुत पुराने दिनों से चलता आ रहा है। इसमें नाजायज़ फायदा अमीर उत्पादक और ट्रेडर लेते हैं। किसान का जो फायदा है, किसान जो उत्पादक है, उसको जो फायदा मिलता है, उससे कही ज्यादा फायदा बीच में जो ट्रेडर है वह कमाता है, जो बिचौलिया है, वह कमाता है।

सजा कहां है? बिचौलियों को कौन-सी सजा है?

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश): सजा गरीब को मिलती है। किसान जब अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है तो दाम गिर जाते हैं। उसको सजा मिलती है।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: किसान को सजा मिलती है। किसान को सजा जरूर मिलती है और बिचौलियों को ज्यादा मिलता है। बिचौलिये जो हैं वे ज्यादा पैसा कमाते हैं।

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल): किसान को सजा मिलती है, बिचौलियों को मजा मिलता है।

†ڈپٹی چیئرمین : کسان کو سزا ملتی ہے بچولیئے کو مزا ملتا ہے ۔

उपसभाध्यक्ष (श्री वी॰ नारायणसामी): अहलुवालिया जी, यहां बोलिए।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: बात सही है। यह महंगाई का कलंक है। तब तक नहीं मिट सकेगा इस भारत की पावन, पवित्र भूमि से जब तक इस देश से गरीबी का कलंक नहीं मिटेगा और गरीबी को मिटाने के लिए हमारे पूर्व पुरूषों ने हर वक्त कहा है कि सिर्फ इस महंगाई को पकड़कर मत रखो, कीमतों को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है, पर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जब खरीद करने वाले, खरीदने वाले की जेब में पैसे आयेंगे तो उसे महंगाई महसूस नहीं होगी। हमें पुराने जमाने का पीछे का कोई बुजुर्ग मिल जाता है तो कहता है कि साहब आधे रुपये में तीन पसेरी चावल मिलता था। अब न तो आधा रुपया रहा न तीन पसेरी रही। पहले लोग मुट्ठी भर पैसे लेकर जाते थे और बोरी में अनाज लाते थे, और आज बोरी में पैसे लेकर जाते है, मुट्ठी में अनाज लाते हैं। इसके पीछे सिर्फ महंगाई जूड़ी हुई है, इसको हम दोष नहीं दे सकते। हम जब तक अपने देश की रूरल पापूलेशन की परचेजिंग पावर को नहीं पढ़ाएंगे, उनकी खरीद करने की क्षमता को नहीं बढ़ाएंगे तब तक महंगाई का स्तर यूं ही हमारे सीने पर चुभता रहेगा। हम जब किसानों के बीच बैठते हैं तो वे इसी तरह का भाषण देते है कि साहब आपकी अनाज की कीमत तो आपको मिलती नहीं पर सब्सिडाइज्ड रेट पर आपके गांव में ही वही अनाज बिकता है और वहां सब्सिडी दी जाती है उनको! किनको! जो निठल्ले हैं, जो खेत मे काम नहीं करते, जो कारखानों में काम नहीं करते। इस तरह का प्रचार वहां होता है और उस पर हम कहते है कि साहब खरीफ की कीमत, जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वह बढ़ाया जाए और इसको जायज समझा जाता है। पीछे सरकार ने इसको जायज समझते हुए गेहूं की 20 परसेंट प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाई और चावल की 21 परसेंट बढ़ाई। आखिर इस सब्सिडी के माध्यम से सपोर्ट करते–करते कितने दिन तक हम समाज को चलाते रहेंगे। मैं सहमत हूं कि महंगाई समाज में है। क्यों है? क्योंकि गरीबी है। बेकारी है। हम जब तक अपने गांव के, शहर के बेकार नौजवान को नौकरी नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, जब तक उनके घर में धन का प्रवेश नहीं होगा जब तक उनकी खरीद की क्षमता नहीं बढ़ेगी तब तह यह महंगाई चुभती रहेगी। मैं वैसे, आंकड़ों में पड़ना नहीं चाहता। अभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कहा जा रहा था। सार्वजिनक वितरण प्रणाली की अभी नयी जो दुकानें खोली गयीं, टारगेट था उसका 10 या साढ़े 10 हजार और करीब 11,681 दुकानें खुल चुकी हैं। इनके माध्यम से अनाज पहुंचाया जा रहा है। किंतु देखा क्या जाता है कि हम एक तरफ दबाव देते हैं कि सरकार की जो मशीनरी है व जो प्रोक्योर करती है अनाज तो उसकी कीमत बढ़नी चाहिए और हम उसको बढ़वा लेते है और हम देहात में जाकर देखते हैं कि उससे सस्ता अनाज मिलता है। हम सरकारी खाद्यान्नों को भरने के लिए जबरदस्ती सरकार को मजबूर करते हैं कि आप अपना प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाइये। पर फुटकर में जब हम अनाज खरीदने जाते हैं तो हमें सस्ता मिलता है। आखिर यह फर्क क्यों है और ये कौन हैं। इस पर भी इंक्वायरी की जाये कि ये कौन हैं। बीच में बिचौलिए जो हैं, जो सरकार का सामान, गांव का सामान, अन्न बाजार के जो बाजार हैं वहां पहुंचाते हैं। किसानों को कुछ पैसा देकर सारा माल अपने स्टॉक में रख लेते हैं और वही सरकार को बेचते हैं। उसी में फायदा उठाते हैं। इस सदन में इन पर कई बार बहस हो

† t[ ] Transliteration in Arabic script.

[श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया]

चुकी है। महंगाई का एक और कारण होता है कि जब देश आत्म-निर्भर न हो, उतनी उपज न हो, बाहर से इंपोर्ट करते हों, पर ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा देश खाद्यान्न के बारे में, आत्म-निर्भर है। हम इस अवस्था में हैं कि हम गेहूं, चावल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और किसानों की बहुत दिनों की एक मांग थी कि हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाकर बेचने का अधिकार दिया जाए और अभी 21 तारीख को राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सब राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे प्रतिबंन्ध उठा लिए जाएं और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर वे अपना अन्न बेच सकें। अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेच सकें, उसका बंदोबस्त किया जा रहा है और आखि जब देखा जाएगा कि बीट प्रड्यूसिंग एरिया का बीट एक ऐसे इलाके में जा रहा है जहां बीट प्रोड्यूस नहीं होता है, पर वहां बीट कंजुमर्स हैं तो वहां निश्चित उनको राहत मिलेगी। ये बिचौलियों ने जो आज हथकंडे अपनाए हुए थे और जो पिछले दरवाजे से लाकर माल की सप्लाई करते थे वे बंद हो जायेंगे। किसान खुद अपना माल ले जाकर दूसरे गांव में बेच सकेगा। इन चीज़ों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो मैं समझता हूं कि एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप करने से बेहतर यह होता कि हम इसके लिए एक सही रास्ता निकालते कि इस देश की 88 करोड़ जनता का भरण-पोषण करने के लिए हम क्या रास्ता निकालें और वेज एंड प्राइस का स्पाइरल जो है वह कैसे रोका जा सके। यह कंज्यूमर प्रणाइस इंडैक्स या होल सेल प्राइस इंडैक्स यह जो तिरछे रूप में ऊपर की तरफ भागता है इसको कैसे पकड़ा जा सकता है, इसके लिए सोच-विचार करने की जरुरत है। न कि हम एक-दूसरे पर कीचड़ उछालें कि आपकी इन नीतियों के कारण यह हो रहा है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: नीतियों के कारण तो हो ही रहा है।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: हां, आप भी बैठ कर नीतियां दिखा दीजिए। आपने अपनी नीति दिखाई सारा कंट्रोल करने के लिए उसका जवाब मिल गया। यह कहना आसान होता है टेबल के उस तरफ बैठ कर कि आपकी नीतियों के कारण हो रहा है। लेकिन जब देश की 88 करोड़ जनता का भविष्य आपके हाथों में होता है, जहां कि अमीर, मध्यम और गरीब हर तरह के लोग हैं, उनका जब भरण-पोषण और 88 करोड़ में से करीब 10 करोड़ बेकार नौजवान जिनके हाथ मे रोज़गार नहीं, जिनको रोज़गार देने के लिए हमें सोचना है, उसके लिए कोई रास्ता ढूंढना है वह नहीं करके हम अगर आरोप और प्रत्यारोप की एक नई शुरुआत करें तो ग यही होगा कि हम इस देश के उन लोगों के भविष्य के बारे में, उसकी बीमारी के इलाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, खाली उसकी बीमारी का प्रचार कर रहे हैं, हम प्रचार करते रहेंगे। उसका किसान बीमार है, बीमार है। अगर बीमार है तो उसका इलाज करो। उसका इलाज क्या है? इलाज क्या है कि राष्ट्र का निर्माण करो। राष्ट्र का ऐसा निर्माण करो कि पूरा राष्ट्र एकजुट होकर सारे देश की जनता की परचेज़िंग पावर कैसे बढ़ सके, उसका एक रास्ता निकालें। पर यहां तो इसकी पालिसी के खिलाफ इसलिए बोलना है क्योंकि यह रूलिंग पार्टी की पालिसी है। मेरी पालिसी नहीं है और हो सकता है कल गद्दी में वे आ करके बैठें और वे भी वही पालिसी अपनायेंगे। पर इन चीजों पर विचार न करके हम सिर्फ महंगाई ही कर रहे हैं। महंगी पर विचार नहीं कर रहे हैं। महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई गरीबी से जूड़ी हुई है। सब से पहले देश की गरीबी दूर करो और देश की गरीबी जिस दिन दूर हो जाएगी उस दिन महंगाई भी दूर हो जाएगी। धन्यवाद।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, श्री जगदीश प्रसाद माथुर जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य और अच्छे नेता है, मैं उनकी कद्र करता हूं। हालांकि उनकी भावनाओं और विचारों से प्राय: मैं सहमत नहीं होता हूं, लेकिन आज मैं उन्हें धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने इस गंभीर विषय को इस सदन में उठाया।

इस बढ़ती हुई महंगाई के बारे में श्री माथुर जी की जो चिंता है, वह पूरे राष्ट्र की चिंता है और इस पूरे सदन की चिंता है। मान्यवर, मुझे अफसोस है अहलुवालिया जी इसे अन्यथा नहीं मानेंगे, इस बढ़ती हुई महंगाई के बारे में सरकार को कोई चिंता नहीं है क्योंकि ऐसे गंभीर विषय पर जब इस सदन में चर्चा हो रही है तो यहां वित्त मंत्रीजी नहीं हैं। बड़े मंत्री जी हो सकता है बजट की तैयारी में लगे हों, तो कम-से-कम छोटे वित्त मंत्रीजी को सदन में रहना चाहिए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: मिनिस्टर सिविल सप्लाइज उपस्थित हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION AND.MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): I am very much here.

श्री इश दत्त यादव: हम सदस्यों की जो भावनाएं हैं, हमारे जो सुझाव हैं, हालांकि खाद्य मंत्रीजी और दूसरे मंत्री

बैठे हैं और हो सकता है वह हमारी बात वित्त मंत्री जी तक पहुंचा दें, लेकिन अगर वह स्वयं बैठकर हमारी बात सुनते तो हो सकता है हमारे तर्क में कोई विशेष बल रहता और वह उस पर विचार करते।

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो चिंता प्रकट की है, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता और मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी और निकम्मापन है कि बजट आने के पहले वह सामानों का दाम बढ़ा देती है। पेट्रोलियम पदार्थों के दम बढ़े, रसोई गैस के दाम बढ़े, चीनी के दाम बढ़े। मान्यवर, यह सही है कि यह सरकार अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से देश के हित में कोई बात न सोचती है और न करती है। मान्यवर, मैं यह साफ-साफ इल्जाम लगाने को तैयार हूं कि सरकार के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक का दबाब है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के दबाब के कारण सरकार बराबर महंगाई इस देश के अंदर बढ़ती चली जा रही है।

मान्यवर, हमारे मित्र अहलुवालिया जी कह रहे थे कि गरीबी और महंगाई का संबंध है। मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन अगर पर्चेजिंग पावर बढ़ा देंगे और महंगाई उससे ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर गरीबी इस देश से खत्म नहीं होनेवाली है। मान्यवर, महंगाई पर कंट्रोल करने के बारे में इस देश के प्रधान मंत्री जी ने जिस दिन शपथ ली थी, संभवत: उस दिन कहा था कि हम महंगाई सौ दिन में कम कर देंगे, लेकिन जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम जिस तरह बेतहाश बढ़े हैं उसके लिए सिर्फ दाल का उदाहरण लेलें। आज इस गरीब देश में जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो डाक्टर कहता है कि प्रोटीन की कमी है, लेकिन वह बीमार कोई विटामिन नहीं खरीद सकता, दूध की व्यवस्था नहीं कर सकता। डाक्टर कहता है कि फिर दाल की मात्रा बढ़ा दो। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अहलुवालिया जी से पूछना चाहता हूं कि पटना से लेकर दिल्ली तक दाल का क्या रेट है? यह 10 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। मान्यवर, यह अत्यंत ही गंभीर विषय है जिस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): मगर उनकी दाल तो सही गल रही है।

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश): आपकी दाल तो गलती बंद हो गयी जब से आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: ईश दत्त जी, मैं जो दाल खाता हूं, वह बाजार में सबसे सस्ती है और वह है उड़द की दाल।

श्री ईश दत्त यादव: मान्यवर, मैं कह रहा था कि प्रधान मंत्रीजी ने सौ दिन के अंदर महंगाई घटाने के लिए कहा लेकिन महंगाई बेतहाशा उन्होंने बढ़ा दी। मान्यवर, मैं सरकार की प्रशंसा करुंगा यदि जिस दिन प्रधान मंत्री की कुर्सी पर नरसिंह राव जी बैठे, उस दिन इस देश में जो सामानों का मूल्य था, महंगाई जिस स्टेंडर्ड पर थी, उसे उसी स्टेंडर्ड पर ला दें। तब भी वह बधाई के पात्र होंगे वरना महंगाई इस देश के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है।

मान्यवर, मैं आपकी घंटी बजने के पहले बात खत्म करूंगा। मान्यवर, महंगाई खत्म करने के गुर होते हैं, इसके तरीके होते हैं और जिसको देश के अर्थशास्त्री कहते हैं। इस देश के सबसे बड़े राजनेता डा. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि महंगाई पर कन्ट्रोल करने के लिए सरकार को दाम बांधो नीति अपनानी पड़ेगी और दाम बांधो नीति के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। इस देश के अंदर कारखाने के अंदर जो सामान पैदा होता है, अगर उसकी लागत एक रुपया है तो डेढ़ रुपए से ज्यादा हिन्दुस्तान के किसी कोने में वह बिकना नहीं चाहिये और किसान के खेत में जो पैदावार होती है, जब वह किसान के घर से मार्केट तक पैदावार निकलती है तो अगली फसल आने तक दस प्रतिशत से लेकर बीस प्रतिशत तक उसका मूल्य बढ़ना नहीं चाहिये। सरकार ने कभी इस पर अमल नहीं किया। इस देश के जो अर्थशास्त्री कहते हैं और डॉ॰ राम महनोहर लोहिया की जो दाम-बांधो नीति थी उस पर सरकार ने कभी गौर ही नहीं किया। अगर सरकार इस पर गौर करती तो शायद महंगाई पर कंट्रोल होता।

दूसरी चीज, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार फिजूलखर्ची पर नियंत्रण कर दे और जो रुपया बर्बाद होता है अनुपयोगी कामों पर, जिससे कोई लाभ नहीं होता, देश की जिससे पैदावार नहीं बढ़ती, केवल शान-शौकत में खर्चा होता है उस पर अगर सरकार नियंत्रण कर दे तो हो सकता है कि महंगाई पूरी तो नहीं, लेकिन जिस स्टैण्डर्ड पर है उससे आधा कम हो जाएगी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मान्यवर, चाइना का चाइना में नियंत्रण कर दिया पैट्रोलियम पदार्थों पर, सरकारी गाड़ियों पर नियंत्रण कर दिया ताकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर से न मंगाना पड़े और अपनी सरकार सारा पैसा पैट्रोलियम पदार्थों को मंगाने पर खर्च करती है और इसलिए पैट्रोलियम पदार्थ मंगाना पड़ता है कि मंत्री जी की भी एक गाड़ी रहेगी, मंत्री जी के पी.ए. की एक गाड़ी रहेगी, मंत्री के बंगले पर दो गाड़ी रहेंगी और मंत्री जी जब दौरे पर जाएंगे तो इनके साथ पचास गाड़ियां चलेंगी। क्या इस पर नियंत्रण

[श्री इश दत्त यादव]

नहीं पाया जा सकता है? इस तरह की जो फिजूलखर्ची है इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है? मंत्री जी के दफ्तर में चार टेलीफोन, घर पर तीन टेलीफोन रखने की क्या जरूरत है? क्या एक टेलीफोन से मंत्री जी का काम नहीं चल सकता है?.... (व्यवधान).... मोटर गाड़ियों का मैं कह चुका हूं। मंत्री जी के दफ्तर में जाइए...(व्यवधान)...

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): क्या हम लोग वर्कर नहीं हैं? सरकारी गाड़ी कहां पचास चलती है? यह गलत बात आप यहां बता रहे हैं।

श्री ईश दत्त यादव: मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं। आप असलियत को इंकार कर रही है। आप स्वयं दुरुपयोग कर रही हैं शासन के पैसे का।.... (व्यवधान) ....मुझे क्षमा करिएगा यह कहने के लिए। शासन के पैसे का सरकार में बैठे हुए लोग सरासर दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर इस पर नियंत्रण हो जाए तो महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। मैं यह चैलेन्ज के साथ, दावे के साथ कहना चाहता हूं। आपने योजनाएं चला दी इस देश के अंदर, लेकिन उसमें क्या होता है। आपने जैसे आंगनवाड़ी योजना चला दी, प्रौढ़ शिक्षा की योजना चला दी। कितने लोगों को शिक्षित किया है? अरबों-अरबों रुपया इस देश का प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर खर्च होता है। मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव में रहता हूं, मैं जानता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर जो विद्यालय चलते हैं और आंगनवाड़ी चलती है, उसमें अरबों-अरबों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। क्यों नहीं इस पर नियंत्रण करते? अगर सरकार की रुचि हो जाए और सरकार का मन हो जाए तो महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए तमाम उपाय हैं, जिनसे महंगाई पर नियंत्रण पाजा जा सकता है।

मान्यवर, आज आदमी की जिन्दगी जीना दूभर हो गया है। दवाहों के दाम, जबसे आपकी सरकार आई है, 50 गुना बढ़ गये हैं, खाद्य-पदार्थों के दाम 5 से लेकर 25 गुना बढ़ गए हैं, कपड़े के दाम 5 से लेकर 20 गुना बढ़ गए हैं। आप कौनसी राहत दे रहे हैं माननीय मंत्री जी? इसमें हंसने की बात नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत है। आप भी बिहार जैसे गरीब प्रदेश से आती हैं। आप जब अपने क्षेत्र में जाती होंगी तो वहां के गरीबों की पीड़ा और आह आपको सुनने को मिलती होगी। आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए और अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो आपको मंत्रिमंडल से हट जाना चाहिए। इस तरह से संघर्ष करेंगी तभी यह सरकार चेतेगी और महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। चाहे आप इसके लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाइये या अर्थशास्त्रियों की बनाइए, लेकिन इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। अगर इस देश के अंदर महंगाई इस तरह से बढ़ी और मान्यवर, डंकल प्रस्तावों को सरकार ने स्वीकृति दे दी है, क्या अंजाम होने वाला है? इस देश के अंदर पैदावार घटेगी, डंकल प्रस्तावों के लागू होने के बाद इस देश का किसान हतोत्साहित होगा। डंकल प्रस्तावों में जो प्रोविजन किए गए हैं उससे इस देश का किसान भयभीत है। इन सब बातों पर आपको गौर करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन का और आपका ज्यादा समय न लेते हुए फिर आपसे और सरकार से मांग करता हूं कि इस देश की इस ज्वलंत और गंभीर समस्या पर आपको गंभीरता से, शांत मन से, शांत अंत:करण से और सारी दुर्भावनाओं को त्यागकर, कुर्सी से चिपके रहने की भावना को त्यागकर के देशहित और राष्ट्रहित में इस महंगाई को कम करने के लिए जो भी संभव उपाय हों, वह करने चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्य श्री माथुर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, वह महत्वपूर्ण है।

इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने महंगाई के संबंध में अपने विचार रखे, उन विचारों में यह भी बात सभी माननीय सदस्यों ने कही कि 1991 के चुनावों के समय कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र में यह था कि हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे और 1989 में वे हटे तब देश की आर्थिक स्थिति क्या थी और 1991 के चुनावों के समय देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी? जो मजबूत स्थिति कांग्रेस ने अपने शासन-काल में की आज उस घोषणा-पत्र की बात कहने वाले जब सत्ता में आए, उन्होंने उस स्थिति को चौपट कर दिया। जो पूंजी इकट्ठी की थी, उसको चौपट कर दिया। 1991 के चुनाव के बाद जब देश के अंदर नरसिंह राव जी की सरकार बनी, तब देश की स्थिति यह थी कि देश दिवालिएपन की ओर जा रहा था। आज सरकार पर दोष देने के बजाए, सरकार ने उपाय किए हैं, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, लेकिन महंगाई बढ़ने की बात, अपने कुकर्म जो किए थे डेढ़ साल में उसको नहीं बताते कि महंगाई बढ़ने का मुख्य रीजन यह है। ...(व्यवधान)...

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश): कुकर्म डेढ़ साल के नहीं हैं, आपके 40 सालों के हैं।

श्री मूलचन्द मीणा: 40 साल में अगर हम कुकर्म करते तो इस देश की जनता 40 साल में दो बार हारने के बाद दोबारा लाई है, अब दोबारा आप जनता को महंगाई की बात कर के बहकाना चाहते हैं। आज बी.जे.पी. के तीन सदस्य बोले और केवल किसानों को चावल और गेहूं के ऊपर जो समर्थन मूल्य दिया है, उसका विरोध किया।....(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: समर्थन मूल्य का किसी ने विरोध नहीं किया।

श्री मूलचन्द मीणा: महोत्रा जी ने कहा कि 100 रुपए गेहूं पर बढ़ा दिए, चावल पर 72 रुपए बढ़ा दिए।

प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा: 40 रुपए किसान को देकर 72 रुपए क्यों बढ़ाते हो?

श्री मूल चन्द मीणा: किसान के 100 रुपए बढ़ने का दर्द आपको लटका है इसका मतलब। महंगाई की बात करते हैं केवल वोट के लिए। मैं सदस्यों को अपनी ओर से यह अनुरोध करना चाहूंगा-महंगाई कैसे मिट सके, महंगाई बढ़ने के क्या-क्या कारण रहे। उनमें कोई सुधार किया जाए ताकि महंगाई न बढ़े। ऐसे सुझाव सरकार के सामने पेश किए हैं, जिसमें कि आज जो महंगाई बढ़ने की बात उठती है। यह महंगाई गरीब को महसूस होती है, उसका पता गरीब को लगता है कि महंगाई क्या है। आज महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। जब हनुमान जी लंका गए थे तो रास्ते में सुरसा ने उनको रोका था तथा सुरसा ने अपना मुंह सौ योजन, हजार योजन तक बढ़ाया था उसी प्रकार से महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। इस महंगाई को सरकार ने रोका है। सरकार ने कोशिश तो की है उसको स्थिर करने की। इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है जो भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है उसको स्थिर किया है। कुछ समय से देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है और आज 90 करोड़ के करीब भारत की जनसंख्या होगी तथा महंगाई उसके पीछे-पीछे बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती। या तो हमें इस जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। महंगाई बढ़ने के और अनेक कारण हैं। आज हर व्यक्ति यह चाहता है कि चिकित्सा सुविधा उसको नजदीक मिले, चिकित्सालय हमारे नजदीक खुलें, स्कूल खुलें, हमें गाड़ियों में बैठने के साफ-सुथरे प्लेटफार्म मिलें और गाड़ियां मिलें और हम महंगाई की बात करते हैं। यदि किसी चीज का उत्पादन कम होगा और उसको खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो महंगाई बढ़ेगी।

श्री शिवचरण सिंह: (राजस्थान) खाने-पीने की चीजों का उत्पादन तो बढ़ा है।

श्री मूलचन्द मीणा: उत्पादन बढ़ा है, किसान को दिया है। तो वह बढ़ेगा। यदि किसान को नहीं दें, किसान को नहीं मिले। सौ रुपए गेहूं के ऊपर बढ़ाया, 21 परसेंट चावल के ऊपर बढ़ाया क्या यह नहीं बढ़ाएं गए?

श्री शिवचरण सिंह: आप भी किसान हैं। गेहूं की कीमतें पिछले 40 सालों में किस रेशों में बढ़ी हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री वी॰ नारायणसामी): कांइडली कांक्लूड।

श्री मूलचन्द मीणा: अब जो बढ़ा है उसका विरोध करने की बात है। जो विरोध करते हैं कि महंगाई इससे बढ़ी है, आवश्यकता क्यों पड़ गई। यह देश किसानों का देश है, किसान आधारित देश है। जब तक इस देश का किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक इस देश के अंदर गरीबी दूर नहीं हो सकती है। किसान कितनी मेहनत से खेती करता है, पैदावार करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कहते हैं कि जो बिचौलिया बीच में कमाते हैं, इसको बंद कर दिया जाए। बिचौलिओं पर प्रतिबंध किया जाए, तो बात अच्छी लगती, शोभा देती कि यह लोग वास्तव में चाहते हैं।

श्री शिवचरण सिंह: सरकार की परचेसिंग और सेलिंग प्राईस क्या है, आप अंदाज करिए? किस कीमत पर खरीदती है और किस कीमत पर बेचती है?

श्री मूल चन्द मीणा: गैस सिलेंडर को ही ले लीजिए। आदत पड़ गई है इस देश के आदमियों को कि सब्सिडी से, दूसरे की मरसी के ऊपर जिन्दा रहें। सरकार को गैस सिलेंडर 155 रुपए का पड़ता है। इसको सरकार कितने में उपलब्ध कराती है-90-100 रुपए में। लेकिन यह सब्सिडी तो गरीब को देने के लिए होनी चाहिए मगर वह सबको मिलती है। सरकार को इसमें फर्क करना चाहिए कि जो लोग नीचे स्तर के हैं, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं उनको इस रेट पर मिले और जो इंकम टैक्स पेई हैं उनको अलग रेट पर मिले। इस तरह से गैस सिलेंडर की सब्सिडी उनसे हटा लेनी चाहिए। तो फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए जाएं। इसके अलावा चीनी के भाव और पैट्रोल की कीमत की बात है। दिल्ली की बात हम लें। पैट्रोल और डीजल से इतनी गाड़ियां आज दिल्ली की सड़कों पर चलती हैं। हर आदमी गाड़ी का उपयोग करना चाहता है। इस देश के अंदर तेल इतना पैदा नहीं होता, बाहर से मंगाना पड़ता है। महोदय, अगले 10 साल के अंदर दिल्ली की हालत यह होगी कि आप दिल्ली

[श्री मूलचन्द मीणा]

की सड़कों पर गाड़ी नहीं चला पाएंगे, इतनी भीड़ हो जाएगी गाड़ियों की। महंगाई बढ़ने के बावजूद भी लाखों गाड़ियां हर साल दिल्ली के अंदर बढ़ जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने के बाद भी यह हालत है। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के जो फिजूल के खर्चे हैं उनको रोका जाए और जनता की आवश्यकता की जो चीजें हैं, उन पर उस पैसे को खर्च किया जाए।

महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान में जहां रेतीले टीले हैं, पहाड़ियां हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा आदि इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित दर की दुकानें खोली गई हैं और वहां रहने वाली गरीब जनता को राशन उपलब्ध कराया गया है। इससे महंगाई पर कंट्रोल होगा। आपने अभी 11681 उचित दर की दुकानें खोली हैं। मेरा अनुरोध है कि इससे भी ज्यादा दुकानें आपको खोलनी चाहिए और जहां गरीब लोग बसेरा करते हैं, उन स्थानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दुकानें खोलकर लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही गरीब आदमी इस महंगाई से बच पाएगा।

श्री शिवचरण सिंह: प्रधानमंत्री जी से गेहूं और चावल ऐलॉट करवा दो, तब दुकानें खुलेंगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Singh, let him speak. Let him say whatever he wants to say. Why do you interrupt him?

श्री मूलचन्द मीणा: राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में मिलता है, जाकर देखिए।

श्री शिवचरण सिंह: सारे राजस्थान में गरीब रहते हैं। केवल बाड़मेर, जैसलमेर में देने से नहीं होगा। पूरे 27 जिलों के लिए चाहिए। पिछले साल के मुकाबले आज हालत क्या है?

श्री मूलचन्द मीणा: आप यहां बैठे रहते हैं। आपको देखना चाहिए कि गेहूं मिल रहा है या नहीं?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Meena, you address the Chair, not him.

श्री मूलचन्द मीणा: महोदय, मैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर रहा था। यदि गरीबों को राहत देनी है तो उसके लिए केवल यही माध्यम सरकार के पास बचा है क्योंकि इस देश के अंदर एक ऐसा तबका पैदा हुआ है बिचौलियों का, जो पुराने समय से चला आ रहा है। वे बिचौलिए सरकार को भी धोखा देते हैं और जनता को भी धोखा देते हैं और केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे बिचौलियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और सरकारी दुकानों के माध्यम से लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाए तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। वैसे सरकार इस बात के लिए सचेत है और जिस तरीके से महंगाई 1990 में बढ़नी शुरू हुई थी, 1991 में इस सरकार के बनने के बाद उसमें स्थिरता आई है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इन गरीबों के लिए, इस देश की गरीब जनता के लिए अच्छी भावना से महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की है। किसानों की उपज का समर्थन मूल्य देने की आवश्यकता है। गेहूं, चावल के साथ साथ अन्य चीजों के ऊपर भी सरकार को समर्थन मूल्य देना चाहिए क्योंकि किसान अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपना पैसा लगाकर जो उत्पादन करता है, जितना उसका खर्च उस को पैदा करने में आता है वह भी उसे पूरा नहीं मिल पाता है। इसलिए सारी चीजों में, चाहे वह सरसों हो, चाहे वह ज्वार हो, चाहे वह जौ हो, चाहे वह चना हो, जो भी उपज किसान पैसा करता है उसको उसका समर्थन मूल्य हर उपज के अनुसार मिलना चाहिए जिस से कि किसान जो खून पसीना एक करके अपनी पैदावार करता है उसका उसे उचित मूल्य मिल सके।

महोदय, कुछ लोग किसानों के समर्थन मूल्य के विरोधी हैं, उनको इस समर्थन मूल्य से दर्द होता है। अभी कुछ समय पहले इसी सदन के अंदर चर्चा आई थी डंकल प्रस्तावों की और हमारे एक साथी ने डंकल प्रस्तावों की बात कही और कहा कि इससे किसानों की उपज को नुकसान होगा। में उससे सहमत नहीं हूं। एक जमाना था जब कि इस देश के अंदर यूरिया खाद पहली बार आई और किसानों को दी गई। हमारे सामने बैठने वाले भाइयों के कुछ नेताओं ने यह बात कही पब्लिक के बीच में जाकर कि कांग्रेस की सरकार किसानों की जमीन को खारा बनाने के लिए यूरिया खाद लाई है। इस से किसानों की जमीन खराब हो जाएगी। उस समय किसान यूरिया खरीदना नहीं चाहता था। लेकिन धीरे धीरे किसान को इस के लाभों के बारे में जब ज्ञान हुआ तो वह यूरिया खरीदने लगा और आज हालत यह है कि यूरिया खाद हमारे यहां कुछ लोग ब्लैक में बेचते हैं। वही डंकल प्रस्ताव का भी होने वाला है। डंकल प्रस्तावों से किसानों को भी फायदा होगा। में चेलैंज के साथ कहता हूं कि जो ये लोग कहते हैं कि किसान बीज नहीं रख सकेगा, यह प्रतिबंध है, मैं समझता

* English translation of the original speech delivered in Tamil

हूं कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं चेलैंज करता हूं कि कोई बता दे कि डंकल प्रस्तावों में बीज किसान नहीं रख सकता, ऐसा कहां पर लिखा है? (व्यवधान)

महोदय, डंकल प्रस्तावों के अंदर किसान को वाजिब मदद मिलेगी। किसानों की पैदावार अच्छी होगी। जो बिचौलिए हैं वह दूर होंगे। इस से किसान खुशहाल होंगें, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे। में सरकार से निवेदन करता हूं कि गरीब जनता के हित को देखते हुए महंगाई पर कंट्रोल करे। धन्यवाद।

*SHRITINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I whole-heartedly welcome this resolution moved by Shri Mathur for it calls upon the Government take effective measures to check the price rise. If a bachelar like Shri Mathur has to face such problems because of price rise, what would be the fate of a family man?

Sir, I can peel off from my memory what the Congress party and A I A D M K which is ruling Tamilnadu promised to the people. When they joined hands to face the election they said they would roll back the price in 100 days to the level prevailed in 1989. This was their election promise. Now three years have passed. Neither the Congress Government at the Centre nor the AIA D M K Government in Tamilnadu did anything to bring down the prices. On the contrary, they have been vying with each other only to hike price of even essential commodities. If the centre increases the price of a commodity bya rupee, the Jayalalitha Government increases it by two rupees. This is the situation today.

Pre-budget hike has become the order of the day. This Government has hiked the price of almost all essential commodities much before the presentation of Budget. The price of sugar has gone up by 27%, rice by 23%, wheat by 21 % and even the price of cooking gas has gone up by 12%. This has crushed the common man. On seeing the burning anger of the masses over this unprecedented price rise, the Government reluctantly reduced the price of cooking gas by 5 rupees after having increased it by 15 rupees. Even this price varies from place to place. While it is Rs. 88 per cylinder in Delhi the same cylinrder costs Rs. 94 in Madras.

Prices of all the commodities are sky rocketting. Petroleum products which are basic necessities for all vital areas have also been increased considerably. Diesel, which is mostly used by the small and marginal farmers has become so costly that farming has become too difficult. Those farmers dependent on diesel engine for irrigation are feeling helpless to cultivate their lands. The diesel price has gone up by over 13.3%.

The Government of Tamilnadu is competing with the centre in increasing the prices and also various taxes. The land tax has been increased four times and the house tax 6 to 7 times in Tamilnadu. Even the bus fare has gone up by 8 times. This is the sort of Government we have there.

Sir, yesterday there was a news item that the Congress and AIA D M K are going to join hands. I don't know what they intend to do. They are only trying to befool the people once again. Because the election is getting closer, they think by joining hands they can be on the saddle for another term. That is the design they have in mind.

SHRI S. MADHAVAN (Tamil Nadu): It is said that DMK and Congress are negotiating for alliance.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARANASAMY): I request the Hon'ble Member to confine himself to the issue of price rise only.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Sir, I wish to inform the Hon'ble Member and the House that yesterday I didn't go to meet the Prime Minister. It was Mr. Swaninathan, leder of AIADMK in this House and the AIADMK leder in Lok Sabha who met him to revive the alliance. It was reported in the press. I am sure the Hon'ble Member has seen that news.

Anyway, I don't want to go into it now. I am only trying to say how callous the Government has been in letting people reel under such soaring prices. For example, meat which was sold at Rs. 40 a Kg is sold at Rs 100 a Kg today. The price of Chicken has gone up from Rs 28 to 80 and that of fish from Rs. 30 to 80. Whenever we talk of price rise, the centre would readily alttribute it to inflation. But who is responsible for inflation also? What have you been doing all these years; We, in opposition have been telling the Government about the need to check

[Shri Tindivanam G. Venkatraman]

the prices for several years. But the Government turns a deaf ear to all the appeal.

The Government makes tall claims that it has been increasing deamess allowance row and then. But that increase is only a pittance as compared to price rise. Even the third quality rice is sold for Rs. 4.45 Kg. What can a common man do? He won't be left with sufficient money even to buy a loin-cloth. Because the price of clothes has also gone up beyond the reach of common man. The price of clothes has gone up by 11%. They produly say that clothes are exported. But I ask, what for? Indians dont have loin-cloth and you talk of export of clothes so brazenly.

But this Government cannot cheat the people any more. People are eagerly waiting to teach a lesson to them. If things are normal, the General Elections should take place in 1995. But one not be wonderstruk if it is advance. That is the situation today. As I concluded, I appeal to the centre to take immediate steps to bring down the prices and save the common man from undue hardship.

4.00 P.M.

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्य महोदय, माननीय श्री जगदीश प्रसाद माथुर जी द्वारा सदन में लाये गये इस संकल्प का अनुमोदन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी बात कहूं उससे पूर्व, माननीय आपूर्ति मंत्री यहां बैठे हैं। खुशी तो इस बात की है कि मंत्री कई बैठे हैं लेकिन साधारण सदस्य, कांग्रेसी साथी कोई नहीं बैठे हैं। मंत्री जी क्या गेहूं के दाम आपने नहीं बढ़ाये, क्या चावल के दाम आपने नहीं बढ़ाये, क्या चीनी के दाम आपने नहीं बढ़ाये, क्या रसोई गैस के दाम आपने नहीं बढ़ाये, क्या पैट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आपने नहीं बढ़ाये? इन सब प्रश्नों का उत्तर केवल एक है, आपने दाम बढ़ाए हैं। दाम आपने क्यों बढ़ाए है? दाम आपने उपभोक्ता वस्तुओं के ही क्यों बढ़ाए और दाम आपने बजट से पांच दस दिन पहले ही क्यों बढ़ाए? यह भी एक प्रश्न है। यह प्रश्न आपकी नीति पर शक पैदा करता है। हमारे माननीय मित्र अहलुवालिया जी यहां बैठे हुए थे, काश वह इस समय सदन में मौजूद होते। मेरी स्वयं की यह प्रवृत्ति है कि मैं जो कुछ करता हूं वह कहता हूं जो ईमानदारी से महसूस करता हूं और इस सर्वोच्च सदन में कहना चाहिये। उन्होंने कहा कि गरीबों की क्रय शक्ति हम बढ़ाना चाहते हैं। क्या हम वास्तव में गरीबी को मिटाना चाहते हैं? अगर महंगाई बढ़े तो बढ़े लेकिन यदि क्रय शक्ति भी बढ़े, आमदनी भी बढ़े, उत्पादन भी बढ़े, रोज़गार भी बढ़े तो मैं समझता हूं कि महंगाई का प्रभाव नहीं हो सकता है या कम हो सकता है लेकिन इस महंगाई का प्रभाव किस पर पड़ेगा? क्या इससे क्रय शक्ति बढ़ेगी या कम होगी? क्रय शक्ति कम होगी, उत्पादन कम होगा और रोज़गार कम होगा। रोज़गार के अवसर तो आपने समाप्त कर ही दिये हैं। मैं अपनी बात को यहां से प्रारम्भ करता हूं कि अभी बहुत दिन से यह जो डंकल प्रस्ताव है, यह बड़ा सिर दर्द बना हुआ है। आप अगर ईमानदारी से यह कह देते कि हमारी मजबूरी है, हम इस डंकल प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और जो भी दबाव हम पर पड़ेगा हम उसे स्वीकार करेंगे और यह हमारे सामने शर्तें हैं, इनको हम स्वीकार करेंगे, हमारे पास कोई उपाय नहीं है या तो देश के लोग हमें कोई उपाय बताएं जिससे हम इन दबावों से मुक्ति पा लें और हम इन शर्तों को स्वीकार न करें, अगर उपाय नहीं देते है तो हम इसे स्वीकार करेंगे तो बात ठीक थी। मगर हमारा आप पर आरोप है कि आपने देश से पूछा भी नहीं, आपने देश के लोगो से सलाह-मशविरा भी नहीं किया, आपने लोगों से उपाय भी नहीं पूछे और आप धोखा देते रहे कि हम नहीं करेंगे, दबाव को नहीं मानेंगे, दबाव में नहीं कर रहे हैं। आज आपके वाणिज्य मंत्री का वक्तव्य छपा है कि हम डंकल प्रस्तावों को अमरीका के दबाव में स्वीकार कर रहे हैं। आज के अखबारों में छपा है। आपने यह जो दाम ये बढ़ा हैं, हमारा आरोप था कि आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करना चाहते हैं। गरीब लोगों को जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राहत मिलती है, आप विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव से उसे समाप्त करना चाहते हैं लेकिन आप धोखा देते रहे, सदन में गलत-बयानी करते रहे सत्य बात यह है कि आप इन चीज़ों के दाम बढ़ा करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करना चाहते हैं। मैं सिद्ध करता हूं कि अभी आपकी नीतियों के झूठ का पुलिंदा माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बढ़ने को मिलता है। आपने हमें कहा कि हमारा सकल गृह उत्पाद बढ़ा है। अगर सकल गृह उत्पाद बढ़ा है तो दाम क्यों बढ़े हैं? आपने यह कहा कि कीमतें हमने रोकी है, महंगाई पर नियंत्रण किया है और एक अंक से सीमित महंगाई हुई है। क्या यह झूठ का पुलिंदा नहीं है। आपने हमें यह कहा कि 10560 नयी राशन की दुकानें खोलने जा रहे है और हमने टारगेट से ऊपर 11681 नयी दुकानें खोली हैं। एक तरफ तो आपने नयी दुकानें खोली हैं लेकिन हो क्या रहा है? आपके इस महंगाई बढ़ाने से दुकानदार कोई माल नहीं उठाएगा और जब बाजार में और सस्ते गल्लें की दुकान पर एक ही भाव पर चीजें मिल रही

है तो कोई भी उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वस्तुएं नहीं खरीदेगा। इस प्रकार से आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्वत: ही समाप्त होने जा रही है। यह आपकी नीयत का पर्दाफाश करता है। आपने जो सदन को गुमराह किया है उस संदेह को यह उजागर करता है वरना तो फिर काहे को दुकानें खोलीं। आपकी मशां सीधी यह थी कि वितरण प्रणाली समाप्त हो जाय। गरीब, निर्धन, बेरोजगार, अलग वेतनभोगी, शोषित, दलित, पीड़ित समाज के लोग जो अधिकतर गांवोन में रहते हैं, उनमें भी ज्यादा संख्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की है उनको राहत दिलाना आपका काम था। लेकिन आज उनको राहत देना बंद हो गया है। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शोषित, दलित, पीड़ित गरीब के दुख दर्द के निवारण की बात करना, उनके कष्ट को दूर करने की बात करना, उनके हित विकास कल्याण की बात करना इस सदन में महज एक रस्म अदायगी रहेगी। क्योंकि न तो उनकी तकलीफें दूर हो रही है न उनको शोषण से मुक्ति मिल रही है, न उनके हित विकास कल्याण हो रहा है। लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि यह सर्वोच्च संस्था के और इसी में हम राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करके कोई निर्णय निकाल सकते हैं। मैं यहां केवल आलोचना ही नहीं करुंगा, बल्कि सुझाव भी दूंगा - अहलुवालिया जी आ गये हैं - कि बेरोजगारी को कैसे समाप्त किया जा सकता है, क्रय शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है, गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। मैं सुझाव भी दूंगा और मेरी यह आदत है कि जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे अनुभव है उसके आधार पर मैं केवल आलोचना ही नहीं करुंगा, सुझाव भी दूंगा। अब इस महंगाई का असर क्या उत्पादन पर नहीं है। यह भी एक प्रश्न है।

मैं आपका इंटरफेरैंस चाहूँगा। मंत्री महोदय पीछे बैठे है और जोर से बात कर रहे हैं। उन्हें प्राइवेट बातें करनी हैं तो बाहर जाकर बात करें। आप उन्हें निर्देश करें यह मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। आप उन्हें यह निर्देशित करें कि वे लाबी प्राइवेट बात करें।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि चलिए पैट्रोल से तो कारें आदि ही चलेंगी लेकिन डीजल से तो ट्रेक्टर भी चलता है और ट्रेक्टर किसान का होता है। हमारे मित्र किसान की बात कर रहे हैं। अगर डीजल के दाम बढ़ाएंगे तो किसान जो ट्रेक्टर का इस्तेमाल करता है जिसमें डीज़ल लगता है उसका उपयोग कम कर पाएगा और उपयोग करेगा तो उसकी लागत के दाम बढ़ेंगे जो अपनी खेती पर लगाएगा और जब उसकी लागत के दाम बढ़ेंगे तो उसका मुनाफा कम होगा। फिर उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी या घटेगी। जिन गरीब लोगों ने, किसानों ने अपनी जमीनों पर सिंचाई के लिए बोरिंग कर रखी है, पानी के इंजन से पानी निकालते हैं, अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो वे उन इंजनों से महंगा पानी निकालेंगे, आबपाशी की लागत ज्यादा लगेगी। तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी या घटेगी। उनकी क्रय शक्ति घटेगी। मान्यवर, अब जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं, या और लोग हैं उन पर इसका सीधा असर है। मुख्य रूप से आदमी की सबसे पहली आवश्यकता होती है रोटी और फिर होता है कपड़ा, उसके बाद मकान, फिर दवा और उसके बाद में शिक्षा, फिर अन्य चीजें। आपने खाने की चीजों के दाम बढ़ा दिये। गरीब आदमी का वेतन, और उसकी आमदनी इतनी है कि सारी अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर सकता और उस पर भी जब खाने की चीजों के दाम बढ़ा दिये तो उसे अपनी कमाई का सारा पैसा केवल खाने पर खर्च करना पड़ेगा। फिर कहां से वह कपड़ा पहनेगा, मकान कहां से बनाएगा, दवा कहां से खरीदकर लेगा और शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा। तो आखिर आप इस मंहगाई को बढ़ाकर क्या करने जा रहे हैं? आप विकास को रोकने।

[उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए]

जा रहे हैं, आप कल्याण को रोकने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपने बड़े झूठ के पुलिन्दे बांधे हैं। आपके आंकड़े जो आए हैं उसमें लिखा है कि पिछले साल ग्रामीण विकास मंत्रालय में कितने लोगों के लिए इम्पलायमेंट निर्धारित किया गया था उससे कम लोगों को रोजगार मिला। अब गांवों में रोजगार नहीं है। महोदय, रोजगार तीन तरह का होता है। एक सेलरीड इम्पलामेंट, नौकरी का रोजगार। नौकरी का रोजगार अब खत्म हो रहा है। नयी नौकरियां मिल नहीं रही हैं।

और पुरानों की छंटनी हो रही है और धीरे-धीरे आप सब की छुट्टी कर डालेंगे। दूसरी तरफ कल-कारखानों में मजदूरी का रोज़गार होता है, चाहे वह माहवारी हो और चाहे रोज़ाना हो, लेकिन वह भी रोज़गार समाप्त हो रहा है, क्योंकि कल-कारखाने अब आदमियों से कम और कंप्यूटर से, बिजली से और मशीन से ज्यादा चल रहे हैं। तो वहां भी रोज़गार नहीं है। तीसरे रोज़गार का जो स्रोत है वह स्वत: रोज़गार है जिसे सैल्फ एंप्लायमेंट कहते हैं। अब स्वत: रोज़गार कहां से मिलेगा। गांवों में स्वत: रोज़गार मिलता था कुम्हार को बरतन बनाने से मगर आपने पॉटरी बड़े-बड़े लोगों को दे दी। उसका रोज़गार खत्म हो गया। गांवों में धोबी को रोज़गार मिलता था कपड़ा धोने का, लांडरी बड़े-बड़े लोगों ने खोल दी और उसका रोज़गार समाप्त हो गया। गांवों में रोज़गार मिलता था मोची को

[श्री संघ प्रिय गौतम]

जूता बनाने से, वह बॉटा, कैरोना और लिबर्टी बनाने लगे, उनका रोज़गार समाप्त हो गया। जो बढ़ई को रोज़गार मिलता था, लोहार को रोज़गार मिलता था वह टिंबर मर्चेंट और आयरन मर्चेंट बड़े-बड़े लोग शहरों में ले गए और उनका रोज़गार समाप्त हो गया। गांवों के अंदर जो लोग जंगल के पत्ते तोड़ करके दोने बर्तन बनाते थे और अब बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां पत्तों को दबा करके पत्तले बनाने लगीं और उनका रोज़गार समाप्त हो गया। अब रोज़गार गांवों में रह कहां गया है? जो प्राकृतिक संसाधन थे जिन पर उन गांवों के गरीबों का सदियों से अधिकार था वह अधिकार भी आपने छीन लिया। वह या तो गांव समाज को दे दिया, या ठेकेदारों को दे दिया या जिला परिषदों को दे दिया और वहां भी उनका जो आमदनी का स्रोत था वह उनसे छिन गया। इसलिए अब स्वत: रोज़गार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इस मंहगाई का क्या असर पड़ेगा? जब विषय आएगा माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करने का तो उस समय कहेंगे। हम चीन का बहुत उदाहरण देते हैं। हमारे मित्र ईश दत्त यादव जी भी दे रहे हैं, अनुभवी आदमी हैं, लेकिन चीन का यह उदाहरण क्यों नहीं देते कि आबादी को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने रोक लगाई है। पहले हमने कहा कि "दो या तीन बच्चे, होते हैं घर में अच्छे" और फिर कहा कि "हम दो हमारे दो" और अब आप यह कानून क्यों नहीं बनाते कि "हम दो और हमारा एक"? आबादी पर कंट्रोल नहीं है तो कहां से काम देंगे? आमदनी नहीं है तो फिर क्या होगा इस मंहगाई से? क्या कोई आपका इधर ध्यान है? अगर आप बड़े ईमानदार हैं, आप पार्टी लाइन से ऊपर उठने की बात क्यों नहीं करते है, कौन सा राज्य होगा, कौन खिलाफ होगा, किसका व्यक्तिगत कानून क्या है, किस पर असर पड़ेगा, मानव कानून से बड़ा कोई कानून नहीं है और मानव अधिकार, मानव सुख और मानव शांति से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चाहे हिन्दू, मुसलमान, सिख, इसाई, पारसी, जैन, बौद्ध कोई भी क्यों न हो। आपने आबादी को नियंत्रित करने के लिए क्या कोई कदम उठाया है, क्या कोई कानून बनाया, क्या कोई घोषणा की और आपने गांवों के लोगों को, गरीबों को रोज़गार देने के लिए कोई कदम उठाए कि कैसे रोज़गार देंगे?

स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मरहूम डाक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब ने वर्द्धा में एक योजना बनाई थी वर्द्धा शिक्षा योजना, जॉब ओरिएण्टेड एजुकेशन क्या आज आपकी जॉब ओरिएण्टेड एजुकेशन है? नतीजा क्या हो रहा है, पढ़ने-लिखने के बाद, डिग्रियां हासिल करने के बाद बेरोज़गार लाखों-करोड़ों की संख्या में लाइन में घूम रहे हैं। आखिर में यह समझ में नहीं आता कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं? केवल राज ही करना चाहते हैं तो राज ईमानदारी से भी किया जा सकता है। मैं आपकी अपनी और निगाह चाहूंगा माननीय सदस्यों की, हम से लोग कहते थे कि सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता। मैं भी पहले ऐसे ही समझता था कि सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता। मैंने एक दिन घी तवा हुआ भी रखा और जमा हुआ भी रखा और इस तरह से सीधी उंगली करके मैंने दोनों बरतनों में से घी निकाला। जमा हुआ घी भी निकाला, उंगली पर आया और तवा हुआ घी भी निकाला, बूंदें आई। निकलता सीधी उंगली से भी है, लेकिन देर से निकलता है। लेकिन घी निकलता जरूर है सीधी उंगली से। आप ईमानदारी से राज कर सकते है। जो दाम आप बजट से पहले बढ़ाते हैं, वह बजट में ही बढ़ाए और ईमानदारी से कहिए कि हम इसलिए दाम बढ़ा रहे हैं। आप सोचते हैं कि इस देश के लोगों की स्मृति बहुत कमजोर है, वे भूल जाते हैं और आप समझते है कि बजट राहत का पेश करेंगे, उसमें दाम कम करेंगे। तो क्या आपने सारे देश के लोगों को बेवकूफ समझ रखा है कि अभी दस दिन पहले जो दाम आपने बढ़ा दिए, उन्हें याद नहीं है कि आपने दाम बढ़ाए थे। वह सब समझते हैं लेकिन हमारी अपनी भी कमजोरी है। हम जब कोई भी देशहित की बात लाएंगें तो हमारे इधर के विरोधी भाई हमको समर्थन नहीं देंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम इसका श्रेय क्यों ले लें। मैं कहता हूं कि, हम पार्टी के बाद में हैं, देश के पहले हैं और जब हम देश के पहले है तो देशहित की बातों पर अगर विपक्षी लोग एकसाथ मिलकर काम करें और आप पर लगावें करें तो आपकी सरकार, आपने जैसे तोड़फोड़ से बनायी है, यह रुकनेवाली नहीं है, लेकिन इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं आप हमारी गलती की वजह से वहां बैठे हुए हैं। इसलिए मैं अपने भाइयों से निवेदन करुंगा कि हम पार्टी-लाइन से ऊपर उठकर बात करें।

मान्यवर, दूसरी बात अभी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मैंने पढ़ी है कि हमारा सकल उत्पाद 1992-93 में 4 प्रतिशत बढ़ा और 1993-94 में यथा-स्थिति रहनेवाला है। जब सकल उत्पाद बढ़ गया, तो फिर इनके दाम क्यों बढ़ा रहे हैं और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम अगर दुनिया में कम हुए हैं तो आप क्यों बढ़ा रहे है? सीधी बात यह है कि आप अमेरिका, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में दाम बढ़ा रहे हैं और अप्रैल में डंकल प्रस्ताव पर जो आप अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, उसमें अपने आकाओं को यह सिद्ध कर दिखाना चाहते हैं कि जो

कुछ तुमने हमें दो-दूनी-तीन पढ़ाया था, वह हमने लागू कर के दिखा दिया।

मान्यवर, कल भी यह एक बिल लाए और वह इंट्रोड्यूस हो गया। मैं पूछता हूं कि यह जो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल है, इसके माध्यम से आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि प्रायवेटाइजेशन के नाम पर आपको फ्री-हैंड मिल जाए और आप मल्टी-नेशनल्स को बुला लें, विदेशी बैंक्स को बुला लें और सारा आधिपत्य उन्हें सौंप दें। फिर उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण आप उनसे कराएं। तो आखिर इस देश के लोगों का क्या होगा? उनको रोजगार कहां से मिलेगा?

मान्यवर, मुझे अपने देश के लोगों पर हंसी आती है। हमारे देश के लोग पीते हैं कोका कोला, पेप्सी कोला और इन्हें बनाने के लिए आप विदेशी कंपनियां बुलाते हैं। मान्यवर, हमारे देश में ऐसे कोला मौजूद हैं कि जिन्हें पीने से गाल लाल हो जाएं और शरीर में ताकत आए। ये हैं दूध कोला, लस्सी कोला, गन्ने का रस कोला, गाजर का रस कोला, संतरे का रस कोला, सेब का रस कोला, शिकंजी कोला तो जब हमारे यहां ऐसे-ऐसे मजबूत कोला हैं तो फिर पेप्सी कोला और कोका कोला आप किस लिए ला रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि क्या सरकार के दिमाग का दिवाला निकल गया है कि इतने ताकतवर कोला मौजूद हैं और आप विदेशों से दूसरे कोला मंगा रहे हैं। फिर आप जब सेंट्रल हॉल में बैठते हैं तो लस्सी कोला और दूध कोला पीते हैं, लेकिन देश के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कोका कोला मंगवाते हैं। आप आज यह फैसला क्यों नहीं कर लेते कि कोई मेंबर सेंट्रल हॉल में लस्सी और दूध नहीं पिएगा, सिर्फ कोका कोला और पेप्सी कोला पिएगा।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: महंगा है?

श्री संघ प्रिय गौतम: नहीं है, यदि है तो आप डेढ़ सौ से दो सौ रूपए रोज भत्ता बढ़ा लेते हैं। अभी आपकी अंतुले रिपोर्ट भी आनेवाली है, लेकिन मैं तो उसका आखिर तक विरोध करूंगा।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: आप अपनी पार्टी के नेता से पूछ लो।

श्री संघ प्रिय गौतम: देखिए, हमारी पार्टी के नेता बहुत समझदार हैं। वे तो स्वदेशी के हामी हैं। उन्होंने अपना अलग बजट पेश किया है। आप अपने आकाओं की फिक्र कीजिए और फिर आपका क्या हश्र होगा? मेरे नेता बैठे हुए हैं। उनके सामने बोल रहा हूं। मेरी पार्टी की नीति है स्वदेशी की, जो मेरे देश में चीजें पैदा होती हैं, जो मेरे देश में चीजें बनती है उस पर विश्वास करने की। मेरे देश से चीजें बाहर जाती थी, ढाका की जैसी मलमल दुनिया में कोई बना नहीं सका, कश्मीर की जैसी शाल दुनिया में कोई बना नहीं सका, ईरान के अलावा मिर्जापुर का कालीन जैसा बना नहीं सका, सहारनपुर के शीशम के फर्नीचर जैसा दुनिया में कोई बना नहीं सका, आपके सम्मल के जैसी सींग के खिलौने दुनिया में कोई बना नहीं सका। मेरे देश में इतनी चीजें बनी है, जो दुनिया में कोई बना नहीं सका। मेरे मित्रों, मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा कि मैं जो कुछ कहता हूं अंदर से बोलता हूँ, खाली जुबां से नहीं बोलता हूं।....(**व्यवधान**)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया: यह लाल किला नहीं है।....(**व्यवधान**)....

श्री संघ प्रिय गौतम: यह लाल किला भी हमारे मजदूरों ने बनाया है, जिनको आप भूखा मार रहे हो। इसे आपने नहीं बनाया और न बादशाहों ने बनाया है। यह जो सदन है, जिसमें हम बैठे है, यह भी शोषित, दलित, पीड़ित लोगों ने बनाया है, आप नहीं बैठे थे उस छत पर प्लस्तर करने के लिए। जो मेरे समाज के लोग थे, जो मेरे पुरखे थे, मुझे उनके ऊपर अभिमान है कि उन्होंने यह सब बनाया है। आप जिस पर बैठे हैं, यह फर्नीचर भी आपने नहीं बनाया है, उन गरीबों ने बनाया है। आप उन गरीबों का मजाक उड़ा रहे हो। गरीबों का नाम आपने लाल किले की दीवालों पर नहीं लिखा, जिन्होंने उसे बनाया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय कि सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, हमारा देश पहले भी स्वतंत्र था, लेकिन बहुत समय तक गुलाम हुआ, कहीं फिर इस आर्थिक कमजोरी के कारण गुलाम न हो जाए, सोचने की जरूरत है। यहां तक व्यक्तिगत झगड़े, धर्म, भाषा, संप्रदाय के झगड़े यह तो सारी दुनिया में चलते रहे हैं और चलते रहेंगे और इससे दुनिया का कोई देश नहीं बचा है जैसे-जैसे विकास, विज्ञान का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, लोगों के अंदर आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक अधिकारों, की मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिए इच्छा बलवती होती चली जाएगी और जब उन अधिकारों को वह सामान्य रूप से प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो वह जाति का सहारा लेंगे, धर्म का सहारा लेंगे, पंथ का सहारा लेंगे, भाषा का सहारा लेंगे, क्षेत्र का सहारा लेंगे यह चीज रुकने वाली नहीं है। अगर आर्थिक दृष्टि से हम पूरी तरह से कमजोर हो गए, हमारी आत्म-निर्भरता समाप्त हो गई तो वही हाल होगा जो बहादूर शाह जफर के समय मुगलों का हुआ था कि लाल-किले के अन्दर लाइन लगाकर लोग खड़े होते थे और जब अंग्रेज गवर्नर आता था तो उनकी बेगमें हाथ फैलाकर मांगती थी कि हमको भी पैसे दे दीजिए, हमको भी पैसे दे

[श्री संघ प्रिय गौतम]

दीजिए। यही आपकी नीति के चलते आपका हाल हो वाला है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस क्षे में आज आत्म-निर्भर नहीं हैं, आत्म निर्भर बनना चाहिए आप कहते हैं कि आप आत्म निर्भर हैं, लेकिन बगैर विश्व बैंक से कर्ज लिए आपकी कोई योजना पूरी होती ही नहीं ...(समय की घंटी)...

मान्यवर, चंद सवालों के साथ ही समाप्त कर रहा हूं आप हमेशा सहारा लेते हैं कि हमने विश्व बैंक से ऋण मांगा है। उस ऋण का भी आप दुरुपयोग ही करते हैं। एव उदाहरण देता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में गंगा कैनाल है, गंग नहर है, इसके बराबर समानान्तर नहर बनाने के लि विश्व बैंक ने ऋण दिया तो उसका क्या हाल हुआ वि नहर तो पूरी हुई नहीं, पुल पूरे हुए नहीं और हर दस मील के बाद फर्स्ट क्लास गैस्ट-हाउस, रेस्ट हाउस बन गए "मुफ्त की पीते थे मय, और कहते थे कि हां, रंग लाएगी हमारी फाकामस्ती एक रोज"। यह आज स्थिति है, महोदय इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप शास्त्रीजी की तरह हमारे देश के लोगों का सलाह-मशविरा लीजिए राष्ट्रीय मुद्दों पर। लाल बहादुर शास्त्री जी लिया करते थे ...(व्यवधान)...

आप हंस रहे हैं। आप इसलिए नहीं हंस रहे। एव पागल के ऊपर लोग हंस रहे थे तो उस पागल ने कहा वि मेरे ऊपर आप नहीं हंस रहे, इसलिए हंस रहे हैं कि मेरे बिरादरी की तादाद कम है, जब पागलों की तादाद ज्याद हो जाएगी तो आप पर हंसेंगे। और, इसलिए आप हंस रहे हो कि हमारी संख्या कम है, जिस दिन हमारी संख्या इस सदन में ज्यादा हो जाएगी तो हम आपके ऊपर हंसेंगे।...आदरणीय माथुर साहब ने बड़े अदब के साथ कहा है कि आप महंगाई पर नियंत्रण कीजिए और महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए ईमानदारी से आप या तो बता दीजिए, आज जब आप उत्तर दें, कि हमने यह महंगाई इसलिए की, इसलिए दाम बढ़ाए और हम कम नहीं कर सकते तो फिर हम आपको सुझाव देंगे कि आप कम कर सकते हैं। हमारे देश के लोग इतने देशभक्त हैं, हमने वह दिन देखें हैं कि जब हमला हुआ चीन का और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, मेरी बहन बेटियों ने अपने कानों की बालियां उतारकर दे दीं और अपने हाथों की अंगूठियां दे दीं। मेरी बेटियों ने यहां पर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जब हताहत मेरे जवान आते थे रेल गाड़ियों से, वह उनका तिलक करती थीं और कहती थीं कि आप चिंता न कीजिए, आप पंगु हो गए, हम आपसे शादी करेंगी। मेरे देश के लोग बड़े देशभक्त हैं। आप उनके पास जाइए, अपनी अर्थव्यवस्था को सुसंचालित करने के लिए आप देश के लोगों से धन मांगिए, आप उनसे दान मांगिए, दान-बैंक खोल दीजिए, दानवीर हैं इस देश के लोग। लोग कहते हैं कि इस देश में सोना नहीं है, सोना कुवैत से ज्यादा है इस देश में, लेकिन कुवैत में सोना एक जगह गढ़ा हुआ होगा, इस देश के हर घर में, हर कान में, हर गले में, हर हाथ में थोड़ा-बहुत सोना है और बहुत सोना है इस देश में। मैं लक्षद्वीप गया हूं और लक्षद्वीप एक शैडयूल्ड ट्राइबल एरिया है, मैंने कोई महिला ऐसी नहीं देखी, जिसके गले और हाथ में दस-दस चीजें सोने की न हों। लक्षद्वीप, जो शैडयूल्ड ट्राइबल एरिया है, मैंने एक-एक जगह देखी है, अपनी आंखों से देखा और कोई ऐसी शादी वहां नहीं होती जिसमें दस, बीस, पचास, सौ या दो सौ तौला सोना नहीं चढ़ता। कहां से आता है, कहां जाता है? ...(समय की घंटी)...

तो मेरे देश के लोगों से आप पैसा मांगिए, चंदा मांगिए और विश्व बैंक के कर्जे से मुक्ति पाइए और एक सीमा निर्धारित कर दीजिए कि इतने दिनों में इससे हमें मुक्ति पानी है। खर्चों में कटौती कीजिए और रोजगार देने के लिए, यह जरूरी नहीं है कि आप नए रोजगार दें। नए रोजगार आप कहां से खोदकर लाएंगे, जो जमीन बेकार पड़ी है, जो जमीन पठारी है या जहां पर कुछ हो सकता है, वहां पर लोगों को काम पर लगा दीजिए - नहरें खुदवाइए, बोरिंग कराइए, पानी निकालिए। देश का विकास भी होगा, लोगों को काम भी मिलेगा। जो गोदामों में अनाज पड़ा है, काम के बदले अनाज दीजिए। यह जो आपके लोग भूखा मरते हैं उड़ीसा में और बिहार में, ऐसी नौबत मत आने दीजिए। काम के बदले अनाज दीजिए। जब उन्हें अनाज मिलेगा तो इससे वे लोग महंगाई की मार से बचेंगे। जब उन्हें काम मिलेगा तो उनकी क्रय-शक्ति भी कायम रह सकती है, थोड़ी-बहुत बढ़ भी सकती है। बात वही है कि "वेन देयर इज़ ए विल, देयर इज़ ए वे" राजनीतिक इच्छा-शक्ति होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय श्री माथुर साहब जी के संकल्प का अनुमोदन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, thank you for giving me this opportunity to speak on the very important Resolution moved by Shri Jagdish Prasad Mathur relating to the price situation prevailing in this country and how it is affecting the common man. What was the economic situation before 1989? How the economic situation was managed by the two Governments in 1990 and 1991, till May 1991, is known to everybody. The inflation trend went up to 16.7

per cent and the prices of essential commodities increased. There was no stabilisation on the price front in the market. Even the balance of payment position was not maintained up to the level. The entire economy of this country was in a shambles. After the present Government headed by Shri Narasimha Rao took over in July, 1991, the new economic policy was introduced. Liberalisation was brought about. License Raj was removed. Imports and exports have been made free except for certain items. The Government gave an assurance to the people that they would stabilise the price situation in the country. The inflation rate was 16.7 per cent. It was brought down to 6.4 per cent.

SHRI M.A. BABY (Kerala): Apart from the question of stabilisation in prices, there was a promise made that prices would be rolled back. Please explain what happened to that.

SHRI V. NARAYANASAMY: The hon. Minister will reply to that. I am not the Minister., *.(interruptions)...*

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: आप अलग क्यों बोल रहे हैं। रेट घट जाएं लेकिन प्राईसेज नहीं घटी हैं। इंफ्लेशन का रेट घटा है।...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: I am participating in the discussion on the motion moved by you. I am giving some new points. I cannot answer Mr. Baby. The hon. Minister will answer that point.

The inflation rate was brought down to 6.7 per cent. Now it is about 7 per cent. Since the presentation of the first, the second and the present Budget, the price situation has remained the same. The subsidies that were given in the case of agriculture, petroleum products and even to the fanners was enormous. Take the case of fertilizers. Right from 1980, there was no increase in the price of fertilizers. Hon. Members who have been speaking from the other side have been attacking the Government while they knew what the real situation was like. The farmers want a subsidy on seeds. They want subsidy on fertilizers. They want a subsidy on their products. Apart from that they also want a better price for their commodities. This is the situation. They want subsidy for the purpose of raising the crops. On the other hand they also want a better price for their products when the market trend is not very favourable. It was found that the subsidy that was given to the farmers was not going to them or the people. It was not going to the farmer directly. The fertilizer subsidy that was given by the Government, it was found, had been siphoned off by the fertilizer industry. The farmers were benefited only to a limited extent. Therefore, the Government introduced the dual system. Subsidy will now be given only to the marginal and small farmers. The State Governments have been authorised to distribute this amount. The farmers want subsidy for seeds. They want subsidy for electricity. Whether it is West Bengal, or Kerala or Tamil Nadu or Pondicherry, the farmers do not pay electricity charges up to 25 hp. The farmers use electricity but do not pay for it. When it comes to prices, the farmers say that they want support price for their products. They want a better price for their products in the market. Who will bear this burden? It will have to be bome by the common man. Therefore, there should be a marginal increase in the price to set right the subsidy part of it. Even today the subsidies given by the Government for food, fertilizers and other items has not decreased to a very large extent.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: The industrialists pay you a lot of money. *..(Interruptions)*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SMT. MARGARET ALVA): And nobody pays you!

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I don't want to comment on you. It is very difficult to comment on a person like you. I have high regards for you.

SHRI V. NARAYANASAMY: Day in and day out when the Government goes in for an increase in the prices.. *.(Interruptions)*

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): मजाक तो समझा करो कम से कम।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप ही के संकल्प पर नारायणस्वामी जी बोल रहे हैं।

कुमारी सरोज खापर्डे: इतनी डिग्रीफाईड मिनिस्टर जिस तरीके से मज़ाक कर रही है, थोड़ा समझा करो।

मैंने कहा तो कोई बात नहीं थी। मिसेज अल्वा ने कहा तो you should take it lightly.

श्री मोहम्मद अफ़ज़ल उर्फ मीम अफ़ज़ल (उत्तर प्रदेश): माथुर साहब इस उम्र तक कभी मज़ाक समझे नहीं हैं, गैर-शादीशुदा हैं। मालूम है आपको?

कुमारी सरोज खापर्डे: यह भी कोई उम्र है जिसको आप सीरियसली लें? यह भी कोई उम्र होती है?

ये भी कोई मैदान में उतरे? (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: मुझे नहीं मालूम था कि मैडम आप उतर चुकी हैं (व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: You can have this conversation at your home.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You are speaking about price stabilisation. You please continue.

SHRI V. NARAYANASAMY: I want to continue. But they are disturbing me. I seek your protection.

Whenever the Government goes in for an increase, there is a hue and cry raised by the other side saying that the Government is increasing the prices indiscriminately, that traders are raided. It is only that hon. Member who will rise and say that traders are being raided indiscriminately. At the same time, he is shedding crocodile tears for the poor people.

During the Emergency, so many hoarders, blackmarketeers were taken to task. So many people in this House and outside criticized the emergency. But as far as the price situation is concerned, I say that during the Emergency it was under control and the traders were on their toes. The people were getting the essential commodities at cheaper rates. The people were very happy. Because of the excesses by some police and other officers, Emergency was criticised by the Opposition parties. But the people were getting the essential commodities at cheaper rates.

SHRI M. A. BABY: Please don't justify the Emergency at least now.

SHRI V. NARAYANASAMY: I can give my viewpoint.

SHRI M. A. BABY: When there are other methods to control price rise , don't quote the Emergency. The Emergency was condemned by everybody. Mr. Anthony is here. He spoke against the Emergency in the Guwahati Session of the Congress.

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Baby, I can give my view. This is a Private Member's Resolution and I can give my view. You can disagree with me. You touch your heart and tell me whether prices came down or not during Emergency. You are in the same party. Can you say that during the emergency essential commodities were not available to the people at reasonable prices? Can you say that there was hoarding and black marketing then? No.

SHRI M. A. BABY: I was in the jail during that period.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Mr. Narayanasamy, it is very unfortunate that you are quoting the Emergency. You should be ashamed of it.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, the word "Emergency' is not an untouchable word. You may have your own viewpoint. I want to tell the hon. Minister that the traders and the persons in the business line are trying to increase the prices artificially. They are trying to increase the prices artificially even though the Government has increased the prices marginally. This has to be taken care of. They are the people who are increasing the prices indiscriminately, without keeping the boards outside which show the price and the stock position. They should be taken to task. Whenever we discuss the issue of price situation, a.lot of suggestions will be made by the hon. Members on the other side about petroleum products and gas. About gas, there was a sarcastic comment made by somebody. The hon. Member said that the Government increased the price first by Rs. 15/- and then reduced it to Rs. 10/-. As a matter of fact, the Government is giving more than Rs. 55/- as subsidy on every gas cylinder. Now, the price has been increased only marginally. So far as petroleum products and diesel are concerned, the Government has been importing large quantities of these products because our petroleum reserves are not able to cope with the increasing domestic demand. That has to be balanced.

They have been telling that when the Budget session is on, when the Budget is going to be presented iri the Parliament, before that, the prices of all these items have been increased.

That argument will not hold good for the simple reason that when the Government brings forward a policy, when we bring forward free trade in this country, when we want that the subsidy system has to be slowly eliminated from this country, when we want the industrialists to compete with each other, whether it is the public sector or the private sector, we will have to see that in the free economy we should not discriminate. The people who are in trade, the people who are in business, especially the people who are in exports want to see that there should be free economy in this country. When the liberalisation has been brought, there should not be any control. The control should be the minimum. That liberalisation policy has been brought by the Government. And it has been implemented well. Sir, they have been criticising the new economic policy of the Government. Sir, the foreign exchange reserves which were kept only at Rs. 2,000 crores have today increased manifold. The country is in a better belance of payments position. That is the achievement of the new economic policy that has been brought by the Government. That has been the ahievement of the export and import policy that has been brought by the Government. And in two years, the price situation has been stabilised by this Government. That is the achievement of this Government. But, Sir, ignoring all these aspects, ignoring the achievements of this Government, they are criticising. Sir, today when we go to the rural areas, we find that the purchasing power of even the fanners is very high...

SHRI M.A. BABY: Mr. Narayanasamy, you have mentioned about the balance of payments position. Can you just state whether we would be in a position to make the repayments without any further borrowing? You paint a very rosy picture about the balance of payments position. So far as our study goes, you have to continue to borrow and you are in a terrible debt trap. And that is the fact. And we are going to continue with that trap. So, the rosy picture that you paint about the balance of payments position is totally baseless. It has been proved time and again. That is a fact.

SHRI V. NARAYANASAMY: The hon. Member is an economist. I am not an economist.

SHRI M.A. BABY: I am also not an 11-2 economist. One need not be an economist to understand this.

SHRI V. NARAYANASAMY: I would like to say that no international organisation, whether it is the IMF or the World Bank or the Europoean Cummunity, will come forward and give us loans blindly. Only when they find that your economic situation is strong, only when they find that you are in a position to repay the money, they will be coming and giving the amount. I would like to tell the hon. Member that when they sanctioned 300 million dollars for the Narmada project and they wanted to impose their conditions, we said that we did not want that money. And I would also like to remind the hon. Member that when our hon. Prime Minister went to Davos, when the issue was raised whether we were going to succumb to the pressures of the world Bank and the IMF and accept their conditions this you have been raising in this House day in and day out the Prime Minister made it very categorical to shut all your mouths saying that "we are not going to accept the loans from the World Bank and the IMF at the dictates of those organisations". He said, "if it is suitable to us, if it is acceptable to us, we will take it; otherwise, we do not want that money." That is what the Prime Minister said. It is on record. It is in black and white.

SHRI M.A. BABY: That is right. We are not taking their dictates. We are *suo motu* implementing what they want.

SHRI V. NARAYANASAMY: Earlier you were saying that. Now, you are making this kind of criticism. Any criticism can be made. But it is very difficult to imnprove the economy of a country. You supported a Government which has totally ruined the economy for which you are also responsible, your Party is also responsible. Therefore, I would like to say that the alarming siutation that you have painted about the price situation saying that the prices of all the items have been increased by this Governnment is not there. There is marginal increase after these two years. They cannot blame this Government because Government's policy is to slcwly reduce the subsidy and to make the farmers self-sufficient.

5.00 P.M.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Narayanasamy, have you

[Shri Md. Salim] concluded or would you like to continue?

SHRI V. NARAYANASAMY: I have not concluded because I have to reply to the points raised.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): So, you can continue next time when it is taken up.

The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday, the 28th February.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock, on Monday, the 28th Februrary, 1994